



बाँकेब कथा बाँकेब भाजलेन
जन जन विचार

जन जन की बात जन जन तक

जन जन विचार

साप्ताहिक

WEEKLY TRILINGUAL NEWSPAPER

Language : Hindi, Assamese & English
WEBSITE : www.janjanvichar.in

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

RNI Regd No. ASMUL/25/A2367::Guwahati, Friday, 7 August 2026 :: Year-1 Vol-30 Issue-9 :: शुक्रवार 17 अगस्त 2026। शक संवत 1948। श्रावण। कृष्ण। नवमी। :: पृष्ठ-20। मूल्य - 15 रुपए

जन चिंतन

धनेश्वर चौधरी

बदइंतजामी डुबो रही

असम फिर डूब रहा है। 95 लोगों की मौत, 1.6 लाख से अधिक प्रभावित, 563 गांव जलमग्न और 14 जिले हाई अलर्ट पर। हर साल आंकड़े बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन असम की त्रासदी नहीं बदलती। सवाल यह है—आखिर कब तक?

बाढ़ असम की पुरानी समस्या है, लेकिन क्या हर साल होने वाली तबाही को सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? जब मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश की चेतावनी देता है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी को समय रहते सुरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता? गांव डूबने के बाद राहत शिविर खोलना प्रशासन की मजबूरी हो सकती है, लेकिन बाढ़ रोकने की स्थायी तैयारी क्यों नहीं?

गुवाहाटी जैसे शहरों में बारिश होते ही सड़कें तालाब **शेष पृष्ठ 2 पर**

‘लोन वॉरियर्स’ ने बदली राजनीति

पीके से ओवैसी तक : सिर्फ एक चेहरा, असर बड़ी पार्टियों जैसा

जन जन विचार
...नई दिल्ली

भारतीय राजनीति में लंबे समय से चुनावी सफलता का आधार बड़ी पार्टी, मजबूत संगठन और व्यापक संसाधनों को माना जाता रहा है। लेकिन बदलते राजनीतिक दौर में कुछ ऐसे नेता उभर रहे हैं, जो सीमित संगठनात्मक ताकत के बावजूद अपने व्यक्तिगत प्रभाव, मुद्दों की स्पष्टता और जनता से सीधे संवाद के जरिए राजनीति की दिशा प्रभावित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर, चंद्रशेखर आजाद, जयराम महतो और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसी बदलती राजनीतिक प्रवृत्ति के उदाहरण हैं।

इन नेताओं की खासियत यह है कि इनके पीछे भले ही राष्ट्रीय स्तर का विशाल संगठन न हो, लेकिन इनके नाम की अपनी राजनीतिक पहचान बन चुकी है। संसद हो या विधानसभा, सड़क का आंदोलन हो या सोशल मीडिया—इनकी मौजूदगी अक्सर



इनके दल के आकार से कहीं बड़ी दिखाई देती है।
बांकीपुर ने दिया बड़ा राजनीतिक संदेश
प्रशांत किशोर की राजनीति का सफर इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। लंबे समय

तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश की राजनीति में प्रभाव छोड़ने वाले किशोर ने सक्रिय राजनीति में उतरकर जन सुराज के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। बांकीपुर **शेष पृष्ठ 5 पर**

स्कैम विज्ञापनों से अरबों डॉलर कमा रहा मेटा?

■ रोजाना दिखाए जाते थे 15 अरब तक जोखिम वाले विज्ञापन, 96 प्रतिशत यूजर शिकायतें हुईं नजरअंदाज

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ‘मेटा प्लेटफॉर्म’ पर ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कंपनी के आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से दावा किया गया है कि मेटा को स्कैम विज्ञापनों से हर साल करीब 7 अरब डॉलर की कमाई होती थी। इन विज्ञापनों में कथित तौर पर फर्जी ई-कॉमर्स और निवेश योजनाओं, अवैध ऑनलाइन जुआ तथा प्रतिबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन शामिल थे।

रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 के एक आंतरिक दस्तावेज में अनुमान लगाया गया था कि मेटा के प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं को हर दिन करीब 15 अरब जोखिम वाले स्कैम विज्ञापन दिखाए जा रहे थे। एक अन्य दस्तावेज में यह आकलन सामने आया कि स्कैम और प्रतिबंधित वस्तुओं से जुड़े विज्ञापन कंपनी की कुल वार्षिक आय का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा हो सकते हैं। रिपोर्ट में मेटा के विज्ञापन निगरानी तंत्र पर भी सवाल उठाए

गए हैं। दावा है कि कंपनी किसी विज्ञापनदाता पर कार्रवाई तब करती थी, जब उसकी स्वचालित प्रणाली को धोखाधड़ी होने का कम-से-कम 95 प्रतिशत भरोसा हो जाता था। इससे संदिग्ध विज्ञापनों को रोकने में देरी होने की आशंका जताई गई है। सबसे गंभीर दावा उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को लेकर है। 2023 के एक दस्तावेज के अनुसार, फेसबुक और इंस्टाग्राम उपयोगकर्ताओं ने हर सप्ताह करीब 1 लाख सही स्कैम रिपोर्ट दर्ज कीं, लेकिन कंपनी ने इनमें से लगभग

96 प्रतिशत शिकायतों को नजरअंदाज या खारिज कर दिया। मई 2025 की मेटा सेफ्टी टीम की प्रस्तुति का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के उत्पाद वैश्विक धोखाधड़ी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। अमेरिका में होने वाले सभी स्कैम मामलों में करीब एक-तिहाई मामलों में मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भूमिका होने का आंतरिक आकलन भी सामने आया। मेटा के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने पहले इन दस्तावेजों को कंपनी की

स्थिति का एकतरफा चित्रण बताया था। उनका कहना था कि मेटा धोखाधड़ी और स्कैम से निपटने के लिए लगातार निवेश कर रहा है और ऐसे कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई करना कंपनी की प्राथमिकता है।

फिर भी, सामने आए दस्तावेजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी, विज्ञापन निगरानी और मुनाफे के लिए जोखिमपूर्ण सामग्री को रोकने की इच्छाशक्ति पर बहस छेड़ दी है। अब सवाल यह है कि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और विज्ञापन से होने वाली कमाई के बीच मेटा किस प्राथमिकता देता है।

अप्रैल-मई 2027 से भारत में शुरू होगी पॉलीमर करेंसी

जन जन विचार
...नई दिल्ली

भारत जल्द ही करेंसी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार, देश में पॉलीमर यानी

प्लास्टिक के बैंक नोट अप्रैल-मई 2027 के बीच जारी किए जा सकते हैं। शुरुआत कम मूल्य वाले नोटों से होगी, जिनका रोजमर्रा के लेन-देन में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है।

पॉलीमर नोट सामान्य कागजी नोटों की तरह दिखेंगे, लेकिन इन्हें विशेष प्रकार के प्लास्टिक पदार्थ से तैयार किया जाएगा। इनकी

सबसे बड़ी खासियत इनकी लंबी उम्र और बेहतर टिकाऊपन होगी। पानी, नमी और धूल का इन पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ेगा और इनके जल्दी फटने या गंदे होने की समस्या भी कम होगी।

आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में पॉलीमर

करेंसी का लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है। कई देशों में ऐसे नोट 30 साल या उससे अधिक समय तक सफलतापूर्वक इस्तेमाल किए गए हैं। भारत में खासकर 10, 20 और 50 रुपए के कागजी नोट जल्दी खराब हो जाते हैं, जिससे उन्हें बार-बार बदलना पड़ता है। **शेष पृष्ठ 7 पर**

रोहा पतंजलि योग समिति ने मनाया जड़ी-बूटी दिवस

जन जन विचार
...**रोहा**

पतंजलि योग समिति, रोहा के तत्वावधान में जड़ी-बूटी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन का संदेश देते हुए विभिन्न औषधीय गुणों वाले पौधों का रोपण किया गया।

कार्यक्रम रोहा गोपीनाथ बरदलै विद्यापीठ परिसर स्थित शुष्कान्त डॉ. भूपेन हजारीका मंच पर आयोजित

हुआ। सुबह पांच बजे नियमित योगासन शिविर के बाद समिति के प्रतिनिधियों और सदस्यों ने परिसर में तुलसी, गिलोय सहित विभिन्न औषधीय पौधों का रोपण किया।

समिति के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर जड़ी-बूटी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को औषधीय पौधों के महत्व के प्रति जागरूक करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण



करना तथा पर्यावरण को समृद्ध बनाना है।

कार्यक्रम में नगांव जिला भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, नगांव जिला पतंजलि योग समिति, रोहा तहसील, नगांव महिला पतंजलि योग समिति तथा रोहा आदर्श पतंजलि योग समिति के प्रतिनिधि, सदस्य एवं सदस्याएं उपस्थित रहे।

समिति के सदस्यों ने अधिक से अधिक औषधीय पौधे लगाने और इनके संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने का संकल्प लिया।

नेपाल में बार-बार क्यों भड़क रही सांप्रदायिक हिंसा

जन जन विचार
...**काठमांडू**

नेपाल के सुनसरी जिले में धार्मिक विवाद के बाद भड़की हिंसा ने एक बार फिर देश के तराई क्षेत्र में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। काप्तानगंज में मंदिर के पास तेज आवाज में बज रहे संगीत और एक धार्मिक झंडे को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते पथराव और हिंसा में बदल गया। पुलिस की गोलीबारी में 24 वर्षीय आम प्रकाश मेहता की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया पड़ा और स्थिति नियंत्रित करने के लिए नेपाली सेना को भी तैनात किया गया।

सुनसरी की घटना को केवल एक स्थानीय विवाद मानना आसान होगा, लेकिन तराई क्षेत्र में पिछले वर्षों में सामने आए ऐसे अनेक मामलों ने एक गहरी समस्या की ओर संकेत किया है। बोरगंज, धनुषा, रौतहट और सरलाही जैसे सीमावर्ती इलाकों में धार्मिक जुलूस, झंडे, लाउडस्पीकर और सांशाल मीडिया पोस्ट कई बार तनाव का कारण बने हैं।

सबसे गंभीर सवाल प्रशासन की भूमिका पर है। छोटी-सी घटना के हिंसक रूप लेने से पहले खुफिया तंत्र और स्थानीय प्रशासन क्यों सक्रिय नहीं हो पाते? पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए गैर-घातक उपायों की पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं रहती? हर घटना के बाद कर्फ्यू



और जांच समिति बनाना समाधान नहीं हो सकता।

नेपाल की खुली भारत सीमा भी इस पूरे समीकरण को जटिल बनाती है। तराई में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पुराने सामाजिक, व्यापारिक और पारिवारिक संबंध हैं। साथ ही, दोनों ओर बढ़ती धार्मिक लामबंदी का प्रभाव भी स्थानीय राजनीति पर पड़ रहा है। हालांकि किसी भी सीमा-पार संगठन या राजनीतिक समूह की भूमिका को ठोस प्रमाण के बिना दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन इस बढ़ती संगठित धार्मिक सक्रियता की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

सांप्रदायिक तनाव का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सामान्य नागरिक धीरे-धीरे एक-दूसरे को पड़ोसी नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी

समुदाय के सदस्य के रूप में देखने लगते हैं। सोशल मीडिया की अफवाहें इस खाई को और गहरा करती हैं।

नेपाल को अब हर घटना के बाद आग बुझाने की नीति से आगे बढ़ना होगा। स्थायी अंतर-धार्मिक संवाद, निष्पक्ष पुलिस कार्रवाई, त्वरित और पारदर्शी जांच तथा भड़काऊ अफवाहों पर तत्काल नियंत्रण जरूरी है।

सुनसरी केवल एक हिंसक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यदि प्रशासन समय रहते मूल कारणों पर कार्रवाई नहीं करता, तो छोटे स्थानीय विवाद बड़े सामाजिक संघर्ष में बदल सकते हैं। नेपाल की असली चुनौती धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि ऐसी राजनीति और प्रशासनिक कमजोरी को रोकना है जो पहचान के नाम पर समाज को बांटती है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

बदइंतजामी डुबो रही

बन जाती हैं। नदियों के किनारे अतिक्रमण, कमजोर तटबंध, खराब जल निकासी और अव्यवस्थित निर्माण पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। फिर भी कार्रवाई अक्सर आपदा आने के बाद ही दिखाई देती है। केंद्र से आर्थिक सहायता मांगना

जरूरी है, लेकिन असम को हर साल राहत का पैकेज नहीं, बाढ़ से लड़ने की दीर्घकालिक रणनीति चाहिए। तटबंधों की जवाबदेही तय हो, नदियों और जल निकासी की वैज्ञानिक योजना बने और भ्रष्टाचार या लापरवाही पर कठोर कार्रवाई हो। बाढ़ प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मानवीय तबाही हमेशा प्राकृतिक नहीं होती। अब सवाल राहत का नहीं, जवाबदेही का है।

राशिफल

24 से 30 जुलाई 2026। विक्रम संवत् 2083-मास : आषाढ़, पक्ष : शुक्ल, तिथि : दशमी

मेघ : यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मेहनत का परिणाम भी मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बातचीत से समाधान निकलेगा।

वृषभ : आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठता का सहयोग मिलेगा। व्यापार में सोच-समझकर निवेश करें।

मिथुन : इस सप्ताह नए संपर्क भविष्य में लाभ दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी पर विचार कर सकते हैं। अनावश्यक खर्च से बचें। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें।

कर्क : परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

सिंह : आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की प्रशंसा हो सकती है। व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। धन लाभ के योग हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें।

कन्या : इस सप्ताह योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिल सकती है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष लाभ मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य की चिंता हो सकती है।

तुला : सप्ताह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रहेगी, लेकिन बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। व्यापार में लाभ हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। रिश्तों में पारदर्शिता रखें। खर्च बढ़ सकता है।

वृश्चिक : आपकी मेहनत रंग लाएगी। कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पुराने मित्र से मुलाकात सुखद रहेगी। गुस्से और जल्दबाजी से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

धनु : भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। यात्रा लाभदायक हो सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में बड़ा निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर होगा।

मकर : काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है।

कुंभ : नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वालों को अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। निजी रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से बचें।

मीन : यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

सप्ताह के पर्व/त्योहार

9 अगस्त (रविवार) : कामदा एकादशी व्रत

10 अगस्त (सोमवार) : सोम प्रदोष व्रत

11 अगस्त (मंगलवार) : मास शिवरात्रि व्रत

12 अगस्त (बुधवार) : हरियाली अमावस्या

13 अगस्त (गुरुवार) : श्री विष्णु शिवात्मक अभिषेक आरंभ



● ज्योतिर्विद आचार्य अखिलेश्वर शुक्ल

भाग्योदय : पहला तल्ला, सेंट्रल प्लाजा, एमएस रोड
फैंसी बाजार, गुवाहाटी-781001 मो.-943350 40387

बाढ़ ने खोली असम के आपदा प्रबंधन की पोल

जन जन विचार
... गुवाहाटी

असम में बाढ़ कोई नई त्रासदी नहीं है। सदियों से राज्य की नदियां जीवन और संकट-दोनों का हिस्सा रही हैं। लेकिन हर साल एक सवाल और गंभीर होता जा रहा है-क्या बाढ़ के लिए असम तैयार है, या हम हर बार पानी बढ़ने के बाद ही जागते हैं?

ऊपरी असम में आई हालिया बाढ़ ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया है। भारी बारिश की चेतावनी पहले से थी, नदियों के जलस्तर की जानकारी उपलब्ध थी और मौसम विभाग ने भी संभावित खतरे के संकेत दिए थे। फिर भी कई इलाकों में लोग पानी बढ़ने के बाद फंसे, बचाव दलों के पहुंचने में समय लगा और बड़ी संख्या में परिवारों को राहत शिविरों का सहारा लेना पड़ा। समस्या केवल मौसम की नहीं है। असल चुनौती चेतावनी और कार्रवाई के बीच मौजूद उस खाई की है, जो हर बड़ी आपदा में सामने आ जाती है।

चेतावनी तभी सफल है, जब कार्रवाई पहले शुरू हो
मौसम विभाग का भारी बारिश का पूर्वानुमान देना आपदा प्रबंधन की शुरुआत है, अंत नहीं। असली सफलता तब होगी जब बारिश की चेतावनी मिलते ही प्रशासन यह तय कर सके कि कौन-से गांव डूब सकते हैं, कौन-से तटबंध कमजोर हैं, कौन-सी सड़कें कट सकती हैं और कितने लोगों तथा मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना होगा।

आज जरूरत केवल यह जानने की नहीं कि बारिश कितनी होगी, बल्कि यह जानने की है कि उस बारिश का असर कहाँ और कितना होगा।

इसके लिए असम के प्रत्येक संवेदनशील नदी बेसिन के लिए वैज्ञानिक बाढ़-प्रभाव मॉडल तैयार किए जाने चाहिए। उपग्रह तस्वीरों, भौगोलिक सूचना प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पिछले वर्षों के बाढ़ आंकड़ों को एक साथ जोड़कर ऐसा तंत्र बनाया जा सकता है, जो भारी बारिश का पूर्वानुमान मिलते ही संभावित प्रभावित क्षेत्रों का नक्शा तैयार कर दे।

यानी प्रशासन को पानी आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पानी आने से पहले नाव, बचाव दल, दवाइयाँ, भोजन और संचार व्यवस्था प्रभावित क्षेत्रों के नजदीक पहुंच जानी चाहिए।

बचाव अभियान 'बाढ़ में' नहीं, 'पहले' शुरू हो

किसी भी आपदा के शुरुआती 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यही वह समय होता है जब त्वरित बचाव अभियान कई जिंदगियाँ बचा सकता है। इसलिए आपदा प्रबंधन का मॉडल प्रतिक्रियात्मक नहीं, पूर्व-सक्रिय होना चाहिए। जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा पहले से स्पष्ट है, वहाँ नावों, मोटरबोट, प्रशिक्षित बचावकर्मियों, चिकित्सा दल और जरूरी सामान की तैनाती पहले से होनी चाहिए। हर बार जिला मुख्यालय से संसाधन भेजने की व्यवस्था पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। असम जैसे विशाल और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया केंद्र मजबूत करने होंगे।

असम में खतरा सिर्फ बाढ़ का नहीं

असम की आपदा प्रबंधन नीति को केवल बाढ़ तक सीमित रखना खतरनाक होगा। राज्य देश के अत्यधिक भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। भूकंप का खतरा हमेशा मौजूद है। इसके अलावा औद्योगिक दुर्घटनाएँ, बांध विफलता, रासायनिक रिसाव, जैविक आपातस्थिति और अन्य गंभीर संकट भी सामने आ सकते हैं।

इसलिए राज्य को 'हर तरह की आपदा के लिए तैयार' मॉडल अपनाना होगा।

इसके दो महत्वपूर्ण पहलू हैं- भौतिक तैयारी और मानसिक तैयारी।

भौतिक तैयारी में प्रशिक्षित कर्मचारी, बचाव उपकरण, मजबूत संचार व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएँ और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचा शामिल हैं। वहीं मानसिक तैयारी का अर्थ है कि प्रशासन, पुलिस, बचाव दल और आम नागरिकों को पता हो कि संकट के समय क्या करना है।

यह क्षमता आपदा आने के समय नहीं बनती। इसके लिए नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल जरूरी हैं।

असम के लोग हर बार बनते हैं पहले मददगार

हर आपदा के बीच असम की एक तस्वीर बेहद प्रेरक होती है- आम लोगों की ईसानियत।

सरकारी मदद पहुंचने से पहले स्थानीय युवक नाव लेकर निकल पड़ते हैं। स्वयंसेवी संगठन राहत सामग्री जुटाते हैं। छात्र संगठन सामुदायिक रसोई चलाते हैं। लोग अपने घरों और संसाधनों को जरूरतमंदों के लिए खोल देते हैं।



भारी बारिश के बाद गुवाहाटी की जलमग्न सड़क से पानी के बीच रिक्शा खींचकर गुजरता एक रिक्शा चालक।

यह मानवीय संवेदना असम की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसके साथ एक असहज सवाल भी जुड़ा है-क्या समाज की यह अद्भुत क्षमता कभी-कभी सरकारी व्यवस्था की कमियों को ढक देती है?

जनता की मदद सरकार की ताकत बननी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी का विकल्प नहीं।

कल्पना कीजिए कि किसी बड़ी आपदा के समय स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय युवक और आम नागरिक आगे न आएँ। क्या सरकारी मशीनरी अकेले उस संकट को संभाल पाएगी?

इस सवाल का जवाब सरकार को अपनी आपदा प्रबंधन क्षमता मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

राहत शिविर सिर्फ आश्रय नहीं सम्मान का स्थान हों

बाढ़ के बाद राहत शिविरों में पहुंचने वाले परिवार केवल अपना घर नहीं खोते। वे अपना सामान्य जीवन, निजी स्थान, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई भी खो देते हैं।

ऐसे में राहत शिविरों का उद्देश्य केवल लोगों को जिंदा रखना नहीं हो सकता। उन्हें सम्मान के साथ जीने की सुविधा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

कई राहत शिविरों में आज भी भीड़, खराब स्वच्छता, पर्याप्त शौचालयों की कमी, जल निकासी की समस्या, महिलाओं के लिए

निजी स्थान का अभाव और कचरा प्रबंधन की कमजोर व्यवस्था जैसी समस्याएँ सामने आती हैं।

गंदे पानी और अस्वच्छ वातावरण के कारण डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, त्वचा रोग और अन्य संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

एक आपदा से बचकर आए लोगों को राहत शिविर में दूसरी स्वास्थ्य आपदा का सामना नहीं करना चाहिए।

आधुनिक राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त शौचालय, बिजली, रोशनी, साफ रसोई, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग स्थान, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था, नियमित स्वास्थ्य जांच और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएँ अनिवार्य होनी चाहिए।

मवेशियों के लिए भी अलग सुरक्षित स्थान होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए अस्थायी कक्षाओं की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

राहत शिविरों में केवल जीवन नहीं बचना चाहिए, जीवन की गरिमा भी बची रहनी चाहिए।

तकनीक बनेगी नई ताकत

21वीं सदी में आपदा प्रबंधन केवल नाव और राहत सामग्री तक

सीमित नहीं रह सकता।

ड्रोन उन क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं जहाँ बचाव दलों का पहुंचना मुश्किल है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता बाढ़ के संभावित फैलाव का अनुमान लगा सकती है। उपग्रह तस्वीरें प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति बता सकती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म राहत सामग्री और वित्तीय सहायता के वितरण में पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से दूरदराज के राहत शिविरों तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सलाह पहुंचाई जा सकती है।

असम में एक स्थायी 'डिजास्टर इंटेलिजेंस सेंटर' स्थापित करने की जरूरत है, जो मौसम पूर्वानुमान, नदियों के जलस्तर, उपग्रह आंकड़ों और संभावित जोखिमों को एक साथ जोड़कर वास्तविक समय में प्रशासन को निर्णय लेने में मदद करे।

बाढ़ तय है, लेकिन तबाही तय नहीं होनी चाहिए

जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश और मौसम की चरम घटनाएँ बढ़ रही हैं। ऐसे में असम के लिए पुरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी।

हर साल बाढ़ आएगी-यह असम की भौगोलिक वास्तविकता है। लेकिन हर साल हजारों परिवारों का उजड़ना, बचाव में देरी होना, राहत शिविरों में असुविधा और बुनियादी सेवाओं का चरमराना किसी प्राकृतिक नियम का हिस्सा नहीं है।

अब समय आ गया है कि असम आपदा प्रबंधन की अपनी पूरी सोच बदले।

पूर्व चेतावनी को पूर्व कार्रवाई में बदला जाए।

बचाव दलों को पहले से तैनात किया जाए।

तकनीक को आपदा प्रबंधन की रीढ़ बनाया जाए।

राहत शिविरों को आधुनिक और मानवीय बनाया जाए।

और बाढ़ से आगे बढ़कर हर संभावित आपदा के लिए तैयारी की जाए।

प्राकृतिक आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता। लेकिन अपर्याप्त तैयारी के कारण होने वाली मानवीय पीड़ा को काफी हद तक रोका जा सकता है।

असम की हालिया बाढ़ को केवल एक और आपदा मानकर भूल जाना सबसे बड़ी भूल होगी। इसे आपदा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था में बदलाव का अवसर बनाना होगा।

संपादकीय

भरोसे का संकट

झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 12 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को सरकार ने आखिरकार बातचीत का न्योता दिया है। देर से उठया गया यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन असली सवाल अब यह है कि क्या सरकार छात्रों की बात सचमुच सुनना चाहती है या केवल आंदोलन को शांत करने की औपचारिकता निभाना चाहती है?

सरकार ने पांच या सात छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन छात्रों ने स्पष्ट कर दिया कि संवाद बंद कर्मों में नहीं, कैमरे और मीडिया के सामने होगा। उनकी यह मांग महज जिद नहीं है। यह उस अविश्वास को दर्शाती है, जो भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर उठे सवाल के कारण पैदा हुआ है।

सरकारी नौकरियों के लिए वर्षों मेहनत करने वाले युवाओं को किसी कृपा की जरूरत नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा और पारदर्शी चयन प्रक्रिया का अधिकार है। यदि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत हैं तो सरकार को प्रमाण के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जांच और संवाद का भरोसा दिया है, लेकिन अब युवाओं को केवल आश्वासन नहीं, समयबद्ध जांच और ठोस कार्रवाई चाहिए।

सरकार को यह समझना होगा कि आंदोलनकारी छात्र किसी राजनीतिक दल की भीड़ नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की आवाज हैं। लोकतंत्र में संवाद का सबसे मजबूत आधार पारदर्शिता है।

अवैध खनन के आरोपों की हो निष्पक्ष जांच

असम में आई विनाशकारी बाढ़ ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर बार भारी बारिश को ही तबाही का एकमात्र कारण मानकर जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? डिब्रूगढ़ जिला नागरिक सम्मेलन ने प्रधानमंत्री से ऊपरी असम की बाढ़ में कथित अवैध कोयला, बालू और पत्थर खनन की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। यह आरोप गंभीर हैं और इन्हें राजनीतिक बयान मानकर खारिज करना उचित नहीं होगा।

शिवसागर, चराइदेव, नाजिरा और आसपास के क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ ने हजारों परिवारों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है। यदि वर्षों से चल रहे अवैज्ञानिक खनन, वनों की कटाई और नदियों से अत्यधिक खनन ने पर्यावरणीय संतुलन बिगाड़ा है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि संगठन ने प्रभावशाली लोगों की कथित सल्लिखता और पूर्व शिकायतों पर कार्रवाई न होने के आरोप लगाए हैं। यदि ये आरोप सही हैं तो मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि संगठित संरक्षण और संस्थागत विफलता का बन जाता है।

गौहाटी उच्च न्यायालय में दायर जहानित याचिकाओं और अदालत के निर्देशों के बावजूद यदि अवैध गतिविधियां जारी रहें, तो सरकार को जवाब देना होगा कि निगरानी तंत्र आखिर किसलिए है? बाढ़ को रोकना संभव नहीं, लेकिन मानवजनित तबाही को रोका जा सकता है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार को आरोपों की स्वतंत्र, समयबद्ध और सार्वजनिक जांच करानी चाहिए।

कोरवोट बैंक का छिटकना

जन जन विचार

...नरिज कुमार दुबे

राजनीति में कोई भी दल जब किसी क्षेत्र को अपना अभेद्य किला और वहां के मतदाताओं को अपना स्थायी वोट बैंक मानकर निश्चित हो जाता है, तभी उसकी पराजय की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। लोकतंत्र में जनता किसी की बंधक नहीं होती। वह सत्ता देती भी है और उसी सत्ता के अहंकार को ध्वस्त भी करती है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने इसी लोकतांत्रिक सच को एक बार फिर स्थापित कर दिया है। तीन दशक से अधिक समय तक भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत मात्र एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता की हार है जो यह मान बैठी थी कि कुछ सीटें और कुछ वोट हमेशा के लिए उसके नाम लिखे जा चुके हैं।

बांकीपुर का जनादेश इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी साधारण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं था। यह वही इलाका है जहां मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा, सचिवालय और सत्ता के तमाम केंद्र मौजूद हैं। भाजपा का प्रदेश मुख्यालय भी यहीं है। लंबे समय से यह सीट भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक रही है। ऐसे में यहां मिली हार सिर्फ सीट गंवाने की घटना नहीं, बल्कि सत्ता के आत्मविश्वास पर जनता का करारा प्रहार है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परिणाम के बाद भाजपा के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो गया है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि इस चुनाव ने सबसे बड़ा संदेश यह दिया है कि कोर वोट बैंक भी अब स्थायी नहीं रहा। जिस मतदाता को वर्षों तक पार्टी का अटूट समर्थक माना जाता था, उसने इस बार अपना रुख बदलकर बता दिया कि लोकतंत्र में समर्थन किसी दल की जागीर नहीं होता। मतदाता अब काम, व्यवहार और नेतृत्व की शैली के आधार पर फैसला करेगा, न कि केवल पुराने राजनीतिक रिश्तों के आधार पर।

यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि सत्ता का आत्मविश्वास कई बार अहंकार में बदल जाता है और यही चुनावी हार की सबसे बड़ी वजह बनता है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह कुछ नेताओं के बयान सामने आए, उन्होंने भी यह संदेश दिया कि पार्टी अपने गढ़ को लेकर अत्यधिक आश्वस्त थी। लेकिन जनता ने मतदान के जरिए यह बता दिया कि किसी भी मतदाता को हल्के में लेने की कीमत राजनीतिक दलों को चुकानी पड़ सकती है।

इस हार के पीछे केवल विपक्ष की रणनीति नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर की बेचैनी भी चर्चा का विषय बनी। उम्मीदवार चयन से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक कई फैसलों को लेकर असंतोष की बातें सामने आईं। राज्य की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के अंदर जिस तरह की खींचतान दिखाई दी, उसका असर भी चुनावी परिणामों में झलकता नजर आया। यह संदेश भी साफ है कि मजबूत संगठन होने का दावा तभी तक प्रभावी है, जब तक कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व स्वयं को सम्मानित महसूस करें।

मध्य प्रदेश के दलित उपचुनाव ने भी लगभग यही कहानी दोहराई। भाजपा के लिए यह हार केवल कांग्रेस की जीत नहीं थी, बल्कि उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल खड़े कर गई। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी और मिश्रा समर्थक संगठनात्मक ढांचे का पूरी तरह सक्रिय न हो पाना भाजपा पर भारी पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, पलायन, खाद की कमी और कथित

प्रशासनिक दबंगई जैसे मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। पार्टी ने चुनाव को सरकार के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई बनाने के बजाय स्थानीय जनभावनाओं से जोड़ा और उसी का लाभ उठाया। साफ है कि मतदाताओं ने यहां भी यह संकेत दिया कि किसी एक नेता की राजनीतिक पकड़ या पुराने प्रभाव के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते।

वहीं बांकीपुर का संदेश केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। यह उतनी ही बड़ी चेतावनी राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू.) और देश के अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी है। वर्षों से बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंकों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस उपचुनाव ने संकेत दिया है कि मतदाता अब नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार हैं। यदि कोई दल यह मानकर चल रहा है कि कोई विशेष जाति, वर्ग या क्षेत्र हमेशा उसके साथ रहेगा, तो बांकीपुर का परिणाम उस भ्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त है।

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का महत्व भी केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है। इस परिणाम ने यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में वर्षों से हावी जातीय ध्रुवीकरण के बीच अब विकास, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए भी राजनीतिक जगह बन रही है। भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरी गढ़ में जीत हासिल कर प्रशांत किशोर ने यह साबित किया कि यदि कोई राजनीतिक दल पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक सरोकारों को लगातार उठाता है, तो वह स्थापित दलों के लिए चुनौती बन सकता है। यह जीत भाजपा के लिए सत्ता के अहंकार के खिलाफ चेतावनी है तो राजद के लिए भी संदेश है कि भाजपा विरोधी राजनीति पर उसका एकाधिकार अब निर्विवाद नहीं रहा। यानी यह परिणाम बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक विकल्प के उभरने का संकेत भी देता है।

यही कारण है कि प्रशांत किशोर की जीत को केवल एक चुनावी सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा। इसे बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछली बार उन्हें चुनावी सफलता भले नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया था। अब बांकीपुर की जीत ने उन मुद्दों को राजनीतिक वैधता भी प्रदान कर दी है।

इस जीत का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक महत्व यही है कि यह भाजपा के सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरी गढ़ में हासिल हुई। इससे यह संकेत भी मिला कि यदि कोई तीसरी राजनीतिक ताकत जनता के बीच विश्वसनीय विकल्प बनती है, तो बिहार की परंपरागत द्विध्रुवीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार इस समय नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहा है। एक ओर पुराने राजनीतिक चेहरे अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश में हैं, वहीं दूसरी ओर नई राजनीति की मांग भी लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में बांकीपुर का परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए एक मनोवैज्ञानिक संकेत बन गया है।

बहरहाल, भारतीय राजनीति लंबे समय तक 'कोर वोट बैंक' की अवधारणा पर टिकी रही है। हर दल अपने कुछ सामाजिक समूहों और क्षेत्रों को अपनी स्थायी राजनीतिक पूंजी मानता रहा। लेकिन बदलते समय का मतदाता अब खुद को किसी दल की स्थायी संपत्ति मानने को तैयार नहीं है। वह सत्ता बदलने से भी नहीं हिचकता और नए चेहरे को मौका देने से भी नहीं डरता। बांकीपुर का जनादेश इसी बदलती राजनीतिक चेतना का सबसे सशक्त उदाहरण है।

मेघालय की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी

जन जन विचार
...नई दिल्ली/शिलांग

मेघालय की जेलों में क्षमता से कहीं अधिक कैदियों को रखने का गंभीर मामला सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, मेघालय की जेलों में निर्धारित क्षमता से 63.5 प्रतिशत अधिक कैदी बंद हैं। इसके साथ ही राज्य देश में जेलों में अत्यधिक भीड़ के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। केवल दिल्ली की स्थिति मेघालय से अधिक खराब है।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 तक मेघालय की जेलों की स्वीकृत क्षमता 860 कैदियों की थी, लेकिन इनमें 1,406 कैदी बंद थे। यानी जेलों में उनकी निर्धारित क्षमता से 546 अधिक कैदी रह रहे थे। मेघालय की जेलों में कुल क्षमता के मुकाबले 163.5 प्रतिशत कैदी मौजूद थे।

दिल्ली सबसे आगे, जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर
जेलों में भीड़ के मामले में दिल्ली देश में सबसे ऊपर है। दिल्ली की जेलों की स्वीकृत क्षमता 10,026 कैदियों की है, जबकि वहां 19,512 कैदी बंद थे। इससे दिल्ली की जेलों में अधिभोग दर 194.6 प्रतिशत रही।

मेघालय के बाद जम्मू-कश्मीर 148.3 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 147.1

देश में ओवरक्राउडिंग में दूसरे स्थान पर राज्य, दिल्ली सबसे आगे



प्रतिशत और महाराष्ट्र 143.9 प्रतिशत के साथ क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।

देश भर में 5.11 लाख कैदी
केंद्र के अनुसार, देश की जेलों की कुल स्वीकृत क्षमता 4,53,769 है, जबकि 31 दिसंबर 2024 तक इनमें 5,11,542 कैदी बंद थे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की अधिभोग दर 112.7 प्रतिशत रही। देश की कम से कम 609 जेलों में उनकी निर्धारित क्षमता से अधिक कैदी पाए गए।

आंकड़ों के अनुसार, जेलों की

क्षमता से कुल 57,773 अधिक कैदी देश भर में बंद थे। यह स्थिति जेलों में रहने वाले कैदियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानूनी सहायता और पुनर्वास जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

3.71 लाख विचाराधीन कैदी
केंद्र ने राज्यसभा में यह भी बताया कि देश की जेलों में 3,71,440 विचाराधीन कैदी बंद थे। इनमें से 968 कैदी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479

अथवा पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत रिहाई के योग्य पाए गए थे। इनमें से 627 विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया।

सरकार के अनुसार, शेष पात्र कैदियों की रिहाई में देरी के कारणों के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गृह मंत्रालय को कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी है।

जेल प्रशासन राज्यों की जिम्मेदारी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत जेल प्रशासन और

कैदियों का प्रबंधन राज्य सूची का विषय है। इसलिए जेलों की क्षमता बढ़ाना, भीड़ कम करना और पात्र विचाराधीन कैदियों की समय पर रिहाई सुनिश्चित करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है।

हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में जेलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 608.6 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग उच्च सुरक्षा वाली जेलों के निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास के लिए किया गया है।

सिर्फ जेल नहीं, न्याय व्यवस्था की भी चुनौती

मेघालय की जेलों में क्षमता से 63 प्रतिशत अधिक कैदियों का होना केवल जेल प्रशासन की समस्या नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया की गति, विचाराधीन कैदियों की स्थिति और पुनर्वास व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

जेलों में अत्यधिक भीड़ से स्वास्थ्य सेवाओं, कानूनी सहायता, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुधारात्मक कार्यक्रमों पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में मेघालय के लिए नई जेल क्षमता विकसित करने के साथ-साथ विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटारे और पात्र कैदियों की समय पर रिहाई पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

'लोन वॉरियर्स' ने बदली राजनीति

विधानसभा उपचुनाव में उनकी जीत को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यह सीट लंबे समय से भाजपा के प्रभाव वाली सीट रही है।

बांकीपुर केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं, बल्कि पटना की राजनीतिक धड़कन माना जाता है। शिक्षित मध्यम वर्ग, कारोबारी, नौकरीपेशा लोगों और राजनीतिक रूप से जागरूक मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में लंबे समय तक भाजपा का प्रभाव रहा। ऐसे में पारंपरिक राजनीतिक गढ़ में एक नए राजनीतिक चेहरे की जीत ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या मतदाता अब स्थापित राजनीतिक समीकरणों से बाहर निकलकर नए विकल्पों को भी मौका देने लगे हैं?

प्रशांत किशोर के लिए यह जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले उनकी राजनीतिक यात्रा को लेकर कई सवाल उठाए जाते रहे थे। अब बांकीपुर का परिणाम उनके समर्थकों के लिए यह संदेश बन गया है कि व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड और स्थानीय मुद्दों पर आधारित राजनीति भी

स्थापित दलों को चुनौती दे सकती है।

चंद्रशेखर आजाद की अलग पहचान

उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन से चुनावी राजनीति तक का सफर तय किया। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख के रूप में उन्होंने दलित अधिकार, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। नगोना से लोकसभा पहुंचने के बाद संसद के भीतर और बाहर उनकी सक्रियता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी।

उनकी राजनीति का आधार पारंपरिक जातीय समीकरणों के साथ-साथ आंदोलनकारी तेवर और युवाओं से सीधा संवाद है। यही वजह है कि सीमित संसदीय संख्या के बावजूद उनकी राजनीतिक आवाज काफी प्रभावशाली दिखाई देती है।

झारखंड में 'टाइगर' की राजनीति

झारखंड के जयराम महतो भी इसी श्रेणी के उभरते हुए नेता हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख महतो ने युवाओं, रोजगार, स्थानीय अधिकार और सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है।

उनकी लोकप्रियता में सोशल मीडिया

की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनके भाषण और वीडियो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचते हैं। यही डिजिटल पहुंच उन्हें पारंपरिक राजनीतिक संगठनों से अलग पहचान देती है। एक विधायक होने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव उनके विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं से बाहर दिखाई देता है।

ओवैसी की अलग राजनीतिक मॉडल

असदुद्दीन ओवैसी लंबे समय से भारतीय राजनीति में एक अलग और स्पष्ट राजनीतिक आवाज के रूप में मौजूद हैं। लोकसभा में अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में वे राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ मुस्लिम समुदाय से जुड़े सवालों को प्रमुखता से उठाते हैं।

ओवैसी की राजनीति का सबसे मजबूत पक्ष उनका प्रभावशाली वक्तव्य और मुद्दों पर स्पष्ट रुख है। एआईएमआईएम ने भी उनके नेतृत्व में अपने पारंपरिक आधार से बाहर निकलकर विभिन्न राज्यों में विस्तार की कोशिश की है। हालांकि उनकी राजनीति को लेकर समर्थन और विरोध दोनों तीखे हैं, लेकिन यह भी तथ्य है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक प्रभाव को पार्टी की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।

क्या बदल रहा है भारतीय राजनीति में ?

इन 'लोन वॉरियर्स' की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारतीय राजनीति अब केवल पार्टी संगठन की ताकत से संचालित नहीं होती। सोशल मीडिया, व्यक्तिगत लोकप्रियता, स्पष्ट मुद्दे, आंदोलन और जनता से सीधा संवाद किसी नेता को सीमित संसदीय संख्या के बावजूद बड़ा राजनीतिक प्रभाव दे सकते हैं।

लेकिन इस मॉडल के सामने चुनौती भी कम नहीं है। व्यक्तिगत लोकप्रियता को स्थायी राजनीतिक संगठन में बदलना, अलग-अलग सामाजिक वर्गों को साथ लाना और लगातार चुनावी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता।

फिर भी प्रशांत किशोर से लेकर चंद्रशेखर आजाद, जयराम महतो और ओवैसी तक की राजनीति एक संकेत जरूर देती है-भारतीय लोकतंत्र में कभी-कभी बड़ी राजनीतिक मशीनरी के सामने एक मजबूत चेहरा भी पर्याप्त चुनौती खड़ी कर सकता है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये 'एकल चेहरे' अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को कितनी दूर तक व्यापक राजनीतिक शक्ति में बदल पाते हैं।

सौम्यता और कर्तव्यपरायणता के जीवंत प्रतीक अविकेश गुप्ता

जन जन विचार



...डॉ मुकेश कुमार

मानव समाज में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो अपने पद, प्रतिष्ठा, प्रभाव और अधिकारों के बाह्य आडंबर से पूर्णतः परे रहते हैं। वे अपनी सहजता, सरलता और आचरण की निर्मलता से जन-जन के हृदयों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रशासनिक पद चाहे कितना भी उच्च और अधिकार संपन्न क्यों न हो, यदि व्यक्ति का अंतःकरण विनम्र और हृदय करुणा से पूरित है, तो उसकी वास्तविक आभा और अधिक निखर कर सामने आती है।

पंजाब सिविल सर्विस की अति-कठिन एवं प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण कर वर्तमान में चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू) के निदेशक पद को सुशोभित कर रहे अविकेश गुप्ता एक ऐसे ही विरले और अनुकरणीय अधिकारी हैं। उनके जीवन और कार्यशैली में सादगी, निष्ठा, प्रभु-भक्ति और उत्कृष्ट प्रशासनिक दक्षता का अनूठा मणिकोचन योग देखने को मिलता है। वे यह सिद्ध करते हैं कि एक सच्चा प्रशासक केवल नियमों का पालन करवाने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों को सहेजने वाला लोक-सेवक होता है।

विनम्रता और ज्ञान का अटूट संबंध

प्रशासनिक सेवाओं की चकाचौंध और उच्च दायित्वों के गुरुत्व के बीच अपनी सरलता और सौम्यता को अक्षुण्ण सुरक्षित रखना किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। आप ने अपने व्यवहार से यह स्थापित किया है कि अधिकार और प्रशासनिक शक्तियां व्यक्ति को अहंकार नहीं, बल्कि अत्यधिक विनम्रता प्रदान करती हैं। उनके दैनिक व्यवहार में व्याप्त सहज सौम्यता को देखकर नीतिशास्त्र के उस अमर संस्कृत श्लोक की अनुपूर्व स्वतः ही सुगुंज देने लगती है—

*विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥*

अर्थात् सच्चा ज्ञान व्यक्ति को विनम्रता प्रदान करता है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से समृद्धि प्राप्त होती है, और उस धर्मपरायण समृद्धि से अंततः वास्तविक सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है।

आपकी पूरी जीवन-यात्रा इसी शाश्वत नीति-मूल्य का सजीव उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी अध्ययनशीलता ने न केवल उन्हें सफलता के उच्चतम शिखरों तक पहुंचाया, बल्कि उन्हें स्वभाव से और अधिक शीलवान, नम्र व विचारशील भी बनाया। एक योग्य अध्येता वही है जिसके ज्ञान का प्रकाश उसकी वाणी में मिठास और आचरण में विनम्रता बनकर ढले। संत कबीरदास जी ने ऐसे ही मधुर और संयमित आचरण को मनुष्य का सर्वोत्तम आभूषण मानते हुए लिखा है—

*ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा छोड़ ।
औरन को सीतल करे, आपहुं सीतल होइ ॥*

अर्थात् मनुष्य को अपने अहंकार का त्याग करके ऐसी मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, जो सुनने वाले के हृदय को शांति और शीतलता दे ही, साथ ही स्वयं के मन को भी परम संतोष और प्रसन्नता प्रदान करे। **सहृदयता, संवाद और मानवीय दृष्टिकोण** आपके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी वाणी की इसी अपूर्व मधुरता और मिलनसार स्वभाव से सहज ही सम्मोहित हो जाता है। एक उच्च प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका कार्यालय केवल कागजी औपचारिकताओं, फाइलों और प्रशासनिक आदेशों का स्थान नहीं है, बल्कि वह सहृदयता, संवेदनशीलता और पारदर्शी संवाद का एक पवित्र केंद्र प्रतीत होता है।

अपनी टीम के अधीनस्थ सहकर्मियों से



लेकर अपनी समस्याओं को लेकर आने वाले जनसामान्य को सुनते समय उनकी आंखों में झलकती संवेदनशीलता और धैर्य यह स्पष्ट दर्शाता है कि वे जन-समस्याओं का समाधान केवल कठोर प्रशासनिक नियमों के दृष्टिकोण से नहीं करते, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर उतरकर करते हैं।

सीटीयू के निदेशक के रूप में उनकी कार्यप्रणाली में जहां एक ओर अटूट ईमानदारी, पारदर्शिता और नियम-निष्ठा का सर्वोपरि स्थान है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक से अधिक सुलभ, सुरक्षित और सुचारु बनाने की बहुमुखी सोच भी स्पष्ट दिखती है। एक कुशल प्रशासक के रूप में उनका यह बहुमुखी व्यक्तित्व ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिवेणी संगम का जीवंत परिणाम है।

कर्म ही पूजा : अध्यात्म और

अंतःकरण का संबल

धर्म और अध्यात्म अविकेश गुप्ता के जीवन का कोई बाह्य आवरण या प्रदर्शन का साधन नहीं है, बल्कि यह उनका आंतरिक

संबल और नैतिक मार्गदर्शक हैं। उनकी भक्ति भावना किसी दिखावे की मोहताज नहीं, अपितु उनके दैनिक कर्मों और निर्णयों में सहज ही झलकती है। ईश्वर पर उनकी अगाध श्रद्धा और समर्पण ही उन्हें विषम से विषम परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, धैर्यवान और निस्वार्थ भाव से कार्य करने की आत्मिक शक्ति देता है।

उनके इस भक्ति भाव, कार्य-कुशलता और आत्मिक संतुलन को देखकर श्रीमद्भागवद्गीता का यह अमर श्लोक स्मरण हो आता है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जैसा-जैसा आचरण करते हैं, सामान्य जन भी उसी का अनुसरण करने लगते हैं। वे जो आदर्श या प्रमाण समाज में स्थापित कर देते हैं, समस्त संसार उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करता है।

निष्ठा, ईमानदारी और 'परहित' का संकल्प

अविकेश गुप्ता ने अपने निष्कलंक आचरण से यह सिद्ध किया है कि ईमानदारी केवल एक नैतिक उपदेश या भाषण का विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। आज की भौतिकवादी और प्रलोभनों से भरी दुनिया में एक निष्कलंक, नेक और ईमानदार जीवन व्यतीत करना ही सच्चे अर्थों में वास्तविक राष्ट्र-सेवा है। उनकी इसी

निष्ठा और सच्चरित्रता के कारण उनका व्यक्तित्व संपूर्ण समाज के लिए एक प्रेरणापुंज बन चुका है।

संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है—

परहित सरिस धर्म नहिं भाई ।

पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥

अर्थात् दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप या अधर्म नहीं है।

अविकेश गुप्ता के हृदय में जन-सामान्य के प्रति जो अपार संवेदनशीलता व्याप्त है, वह इसी 'परहित' की भावना से निरंतर सिंचित है। सार्वजनिक परिवहन जैसी अति-महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवस्था के शीर्ष पद पर रहते हुए उनका यह निरंतर प्रयास रहता है कि हर आम नागरिक की यात्रा सुरक्षित, सुलभ, आरामदायक और सम्मानजनक हो। उनकी संवेदनशीलता केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और जीव-मात्र के प्रति एक आत्मीय भाव को समेटे हुए है।

बहुमुखी प्रतिभा और सत्य पर आधारित आधार स्तंभ

बहुमुखी प्रतिभा के धनी अविकेश गुप्ता का जीवन इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि प्रशासनिक दक्षता और आध्यात्मिक सौम्यता एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं। जब कोई प्रशासक भीतर से अध्यात्म-केंद्रित और नैतिक मूल्यों से समृद्ध होता है, तो उसका बाह्य कर्तृत्व और अधिक प्रभावी, न्यायसंगत, पारदर्शी और लोकोपकारी बन जाता है।

चाणक्य नीति में ऐसे बहुमुखी और सच्चरित्र व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः ।

सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ।

अर्थात् सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य के प्रभाव से ही सूर्य तपता है और सत्य से ही पवन बहती है; निःसंदेह संपूर्ण जगत् सत्य के ही आधार पर अश्रित है।

उनका जीवन सत्य, धर्म और ईमानदारी के इसी मजबूत आधार स्तंभ पर टिका हुआ है। वे सफलता की उन ऊंचाइयों को छू चुके हैं जहां पहुंचना अनेक लोगों का स्वप्न होता है, परंतु फिर भी उनकी जड़ें धरातल से गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनका मिलनसार व्यक्तित्व, चेहरे पर बिखरी मंद मुस्कान और हर किसी की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने का भाव उन्हें जन-जन का प्रिय बनाता है।

वृंद कवि ने अपने प्रसिद्ध दोहे में ऐसे ही महान और गंभीर पुरुषों के स्वभाव की महिमा गाते हुए कहा है—

*अति अगाध अति ऊँछरी, नदी कूप सरु बाव ।
सो ताको सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाय ॥*

अर्थात् नदी, कुआँ, तालाब भले ही कितने भी गहरे या लबालब भरे हों, लेकिन किसी प्यासे व्यक्ति के लिए असली समुद्र वही स्थान है जहाँ पहुंचकर उसकी प्यास बुझ जाए। अविकेश गुप्ता का व्यक्तित्व भी उसी विशाल और उदार सागर के समान है, जहां पहुंचकर हर कोई अपने मन की व्यथा, प्रशासनिक समस्याओं और चिंताओं का उचित समाधान प्राप्त करता है। उनकी सौम्यता को कभी दुर्बलता नहीं समझा जा सकता, बल्कि वह उनके अटूट आत्मबल और आचार-विचार की प्रगाढ़ता का सजीव संकेत है।

संक्षेप में कहा जाए तो अविकेश गुप्ता एक ऐसे आधुनिक प्रशासनिक संवाहक हैं, जिन्होंने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से पद की गरिमा को कई गुना बढ़ाया है और अपने सौम्य व्यवहार से लोक-कल्याण के नए एवं उच्च मानक स्थापित किए हैं। उनका जीवन समाज और भावी पीढ़ी को यह अमर संदेश देता है कि यदि मन में प्रभु-भक्ति, हृदय में अपार संवेदनशीलता, कर्म में अटूट ईमानदारी और वाणी में मिठास हो, तो व्यक्ति न केवल प्रशासनिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज के लिए एक युग-निर्माता और प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। ऐसे सरलता के प्रतिमान, मानवीय मूल्यों के संरक्षक और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी पर पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक जगत् को हार्दिक गर्व है।

ग्लासगो से गुजरात पहुंचा राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज

अहमदाबाद 2030 की मेजबानी का औपचारिक आगाज, खेल अवसंरचना और खिलाड़ियों के विकास पर रहेगा जोर

जन जन विचार
...**गांधीनगर**

ग्लासगो में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले शताब्दी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया है। ग्लासगो से राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज गुजरात पहुंचा और गांधीनगर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपा। ध्वज हस्तांतरण के साथ ही अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का आधिकारिक शुभारंभ माना जा रहा है।

ग्लासगो के समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया था। अब यह ध्वज वर्ष 2030 तक गुजरात में रहेगा और अहमदाबाद की मेजबानी की जिम्मेदारी का प्रतीक बनेगा।



39 पदकों के साथ भारत का शानदार प्रदर्शन

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय पैरा-एथलीटों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए सात पदक जीते, जिनमें तीन स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य शामिल रहे।

खिलाड़ियों की मौजूदगी में हुआ हस्तांतरण

ध्वज हस्तांतरण समारोह में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले गुजरात

के खिलाड़ी और पैरा-एथलीट भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि 'टीम गुजरात' अहमदाबाद में 2030

राष्ट्रमंडल खेलों की सफल मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने कहा कि तैयारियां कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स, भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण और गुजरात के खेल विभाग के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाई जाएंगी। उनके अनुसार, ग्लासगो से अहमदाबाद तक 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की यात्रा अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है।

खेल सुविधाओं के विस्तार पर जोर

2030 की मेजबानी को गुजरात केवल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के अवसर के रूप में देख रहा है। सरकार आधुनिक खेल सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और जिला स्तर पर खेल प्रतिभागों को प्रोत्साहित करने पर जोर देगी।

राज्य सरकार जिला खेल परिसरों

के माध्यम से स्थानीय खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने की योजनाओं पर भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों की प्रतिभागों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उपमुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि खेलों में निवेश युवाओं को फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को ओर प्रेरित करेगा। साथ ही यह प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया' अभियान तथा 'नशा मुक्त भारत' की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ध्वज बना मेजबानी के हस्तांतरण का प्रतीक

राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज परंपरागत रूप से मौजूदा मेजबान शहर द्वारा अगले मेजबान शहर को समापन समारोह में सौंपा जाता है। यह केवल आयोजन की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता, मित्रता, सहयोग और निष्पक्ष खेल भावना का संदेश भी देता है।

श्रीलंका दौरा : टीम इंडिया से जुड़े चार युवा गेंदबाज

जन जन विचार
...**कोलंबो**

श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने चार युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम के साथ जोड़ा है। हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, विपराज निगम और शिवांग कुमार को टीम में नेट गेंदबाज के तौर पर शामिल किया गया है। इन खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य भारतीय बल्लेबाजों को श्रीलंकाई परिस्थितियों में स्पिन और अलग-अलग गेंदबाजी शैलियों के खिलाफ अभ्यास कराना है।

चारों खिलाड़ियों के लिए भारतीय टेस्ट टीम के साथ समय बिताना अपने आप में बड़ा अवसर है। भले ही उनके प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की संभावना कम है, लेकिन राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ियों के साथ अभ्यास और ड्रेसिंग रूम के माहौल का

अनुभव उन्हें भविष्य के लिए तैयार करेगा।

हर्ष दुबे विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। वह इस वर्ष अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में पदार्पण कर चुके हैं और भारतीय टीम के साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर भी रह चुके हैं।

तनुष कोटियन मुंबई के ऑफ-स्पिनर हैं और पिछले दो घरेलू सत्रों में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वह 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भी भारतीय टीम में शामिल किए गए थे।

विपराज निगम लेग-स्पिनर हैं और भारत ए टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए भी अपनी प्रतिभा दिखाई है।

वहीं शिवांग कुमार, जो मध्य प्रदेश के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़े रहे हैं। वह इससे पहले भी भारतीय टीम के नेट गेंदबाज रह चुके हैं।

राष्ट्रमंडल खेल : तेरह स्वर्ण में 8 बेटियों के नाम

जन जन विचार
...**नई दिल्ली**

ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का मान बढ़ाया। भारत ने प्रतियोगिता में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। इस उपलब्धि की सबसे खास बात यह रही कि भारत के 13 स्वर्ण पदकों में से 8 स्वर्ण महिला खिलाड़ियों ने अपने नाम किए।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी पदक विजेताओं और दल के प्रत्येक सदस्य को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देश के लिए गर्व का विषय है और उन्हें विश्वास है कि ये खिलाड़ी भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भी देश का नाम रोशन करेंगे।

महिलाओं ने दिखाया दम

भारत के स्वर्णिम प्रदर्शन में महिला खिलाड़ियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। कुल 13 स्वर्ण पदकों में आठ महिलाओं के नाम

होना भारतीय खेलों में महिलाओं की बढ़ती ताकत और बदलती तस्वीर को दर्शाता है। यह उपलब्धि युवा महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का बड़ा स्रोत मानी जा रही है।

मुक्केबाजी में भारत का दबदबा

ग्लासगो में भारतीय मुक्केबाजों ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण शामिल रहे। महिला मुक्केबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पांच स्वर्ण पदक हासिल किए। रिंग में भारतीय खिलाड़ियों की आक्रमकता, तकनीक और आत्मविश्वास ने देश को पदक तालिका में मजबूत स्थिति दिलाई।

जूडो में पहली बार दो स्वर्ण

जूडो में भी भारत ने नया इतिहास रचा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में कुल चार पदक जीते और पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। यामिनी मोर्या ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया।

पृष्ठ 1 का शेषांश...

अप्रैल-मई 2027 से भारत में शुरू होगी पॉलीमर करेंसी

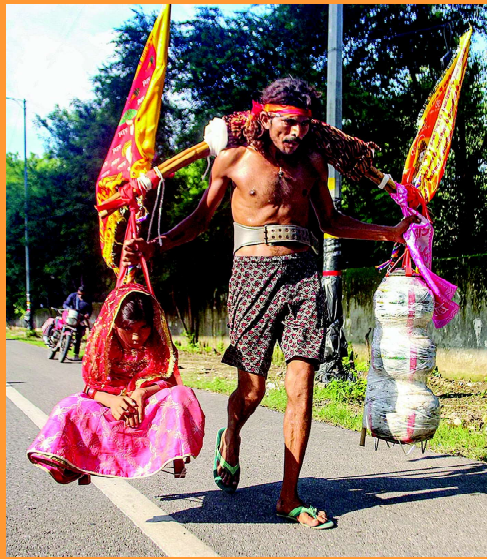
पॉलीमर नोटों में आधुनिक सुरक्षा विशेषताएं शामिल करना आसान होता है। इससे नकली नोट तैयार करना कठिन हो सकता है। साथ ही नोटों की लंबी उम्र के कारण बार-बार छपाई की जरूरत कम होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने बैंक

नोटों की छपाई पर करीब 6,373 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

पॉलीमर नोट आने का मतलब यह नहीं है कि मौजूदा कागजी नोट अचानक बंद हो जाएंगे। दोनों तरह की करेंसी कुछ समय तक साथ-साथ चलेंगी। बदलाव चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और पुराने नोट तब तक प्रचलन में रहेंगे, जब तक उनकी जगह नए नोट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो जाते।

भारत में बड़े मूल्य के नोटों को बंद करने के फैसले पहले भी लिए गए हैं। 1946, 1978 और 2016

में बड़े नोटों को चलन से बाहर किया गया। 2016 में 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट बंद कर नए 500 रुपये के नोट तथा 2,000 रुपये के नोट जारी किए गए। बाद में मई 2023 में आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को 'क्लीन नोट पॉलिसी' के तहत प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया। लेकिन 2027 का बदलाव अलग होगा। यह नोटबंदी नहीं, बल्कि मुद्रा के कागज से पॉलीमर की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की प्रक्रिया होगी।



भक्ति के साथ रिश्तों का सम्मान : मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक कांवड़िया अपनी बेटी को सजी हुई कांवड़ में लेकर चलता नजर आया, वहीं आरती अपनी सास उषा को कंधे पर बैठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटीं।

बिल्वपत्र नहीं मिला तो भी क्या रोटी खाने से बढ़ता है वजन नहीं रुकेगी शिव पूजा



श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिल्वपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन यदि सावन में किसी दिन ताजा बिल्वपत्र उपलब्ध न हो तो भक्तों को पूजा को लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

शास्त्रों में वर्णित मान्यता के अनुसार, पहले भगवान शिव को अर्पित किया गया बिल्वपत्र भी शुद्ध जल से धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः पूजा में चढ़ाए गए फूल-पत्तों का पुनः उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन बिल्वपत्र को इसका अपवाद माना गया है। यदि ताजा बिल्वपत्र आसानी से उपलब्ध हो, तो उसी का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। अन्यथा मंदिर में उपलब्ध अर्पित बिल्वपत्र को श्रद्धापूर्वक धोकर शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति तथा सोमवार को बिल्वपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए आवश्यकता हो तो इन दिनों से पहले बिल्वपत्र तोड़कर रख लेने की परंपरा है। बिल्वपत्र तोड़ते समय श्रद्धालु विशेष मंत्र का जाप भी कर सकते हैं।

मान्यता है कि विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन में नियमित रूप से बिल्वपत्र अर्पित करना शुभ होता है। सामान्य शिव पूजा में पांच या सात बिल्वपत्र चढ़ाए जा सकते हैं। विशेष पूजा के लिए 18 बिल्वपत्रों पर लाल चंदन से 'राम' लिखकर एक-एक करके शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा भी बताई गई है। बिल्वपत्र चढ़ाते समय श्रद्धा और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव भक्त की भावना को स्वीकार करते हैं; इसलिए बिल्वपत्र उपलब्ध न होने पर भी श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कर शिव की पूजा की जा सकती है।

वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के बीच एक सवाल अक्सर सुनने को मिलता है-क्या रोटी खाने से वजन बढ़ता है? कई लोग वजन घटाने के लिए रोटी पूरी तरह छोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट को मोटापे का मुख्य कारण मानने लगते हैं। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है।

वजन बढ़ने या घटने का संबंध केवल रोटी खाने से नहीं, बल्कि पूरे दिन में ली गई कुल कैलोरी, भोजन की गुणवत्ता, रोटी की मात्रा, शारीरिक गतिविधि और जीवनशैली से होता है। सही मात्रा में और संतुलित भोजन के साथ खाई गई रोटी वजन घटाने वाली डाइट का हिस्सा हो सकती है।

रोटी को दुश्मन मानना सही नहीं
गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट के साथ



फाइबर, प्रोटीन और कुछ जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी जरूरत रोजमर्रा के काम और शारीरिक गतिविधियों के लिए होती है।

समस्या अक्सर रोटी से ज्यादा उसकी मात्रा और उसके साथ खाए जाने वाले भोजन से पैदा होती है। यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा रोटियां खाता है और साथ में तली-भुनी सब्जियां, अधिक तेल, घी, मिठाई या मीठे पेय भी लेता है, तो कुल कैलोरी जरूरत से ज्यादा हो सकती है। यही वजन बढ़ने की वजह बन सकती है।

वजन घटाने में रोटी कर सकती है मदद

साबुत गेहूं की रोटी में मौजूद फाइबर पेट को अपेक्षाकृत लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद कर सकता है। इससे बार-बार खाने या अनावश्यक स्नैकिंग की आदत को नियंत्रित करना

आसान हो सकता है।

लेकिन रोटी अकेले संपूर्ण भोजन नहीं है। इसे दाल, चना, राजमा, पनीर, दही, अंडे या अन्य प्रोटीन स्रोतों और पर्याप्त सब्जियों के साथ खाना अधिक संतुलित विकल्प बनाता है। एक सामान्य भोजन की थाली में रोटी के साथ प्रोटीन, सब्जियां और सलाद शामिल करने से भोजन अधिक पौष्टिक और संतुलित हो सकता है।

कौन-सी रोटी बेहतर ?

वजन नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः साबुत गेहूं के आटे की रोटी एक अच्छा विकल्प हो सकती है। कुछ लोग अपनी पसंद और पोषण संबंधी जरूरत के अनुसार मल्टीग्रेन आटे का भी इस्तेमाल करते हैं।

हालांकि, केवल आटे का नाम बदल देने से रोटी अपने आप वजन घटाने वाली नहीं बन जाती। अंततः मात्रा और कुल कैलोरी सेवन महत्वपूर्ण रहते हैं। रोटी पर ज्यादा घी या मक्खन लगाने से अतिरिक्त

कैलोरी बढ़ सकती है। इसलिए वजन कम करने की कोशिश में इसकी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए।

रोटी से ज्यादा जरूरी है पूरी थाली

अगर आपकी थाली में चार-पांच रोटियां हैं और सब्जी में बहुत अधिक तेल है, साथ में मीठा पेय और मिठाई भी है, तो केवल रोटी छोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय भोजन में संतुलन बनाना जरूरी है। एक संतुलित थाली में शामिल हो सकते हैं- सीमित मात्रा में रोटी या अन्य अनाज, पर्याप्त हरी और मौसमी सब्जियां, दाल-चना-राजमा या अन्य प्रोटीन स्रोत, दही या अन्य उपयुक्त डेयरी विकल्प, सलाद और पर्याप्त पानी।

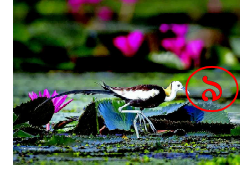
वजन कम करने के लिए केवल रोटी छोड़ देना या बहुत कम खाना सही रणनीति नहीं है। अत्यधिक प्रतिबंध लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते और भोजन के प्रति अस्वस्थ आदतें विकसित कर सकते हैं।



ৰাইজৰ কথা ৰাইজৰ মাজলৈ

জন জন বিচাৰ

Guwahati, 7 August, 2026 Friday :: শুক্লাৰ, শাওণ, কৃষ্ণ পক্ষ, নৱমী, শকাব্দ ১৯৪৮



অৰুণাচলৰ সীমান্তত ভাৰত-চীন সেনাৰ নতুন মুখামুখিৰ দাবী

তাকচিং অঞ্চলৰ ছবি-ভিডিঅ'ক লৈ চাঞ্চল্য, চৰকাৰী নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও নাই

জন জন বিচাৰ ...৫ ইটানগৰ

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উপৰ সোৱণশিৰি জিলাৰ তাকচিং চক্ৰত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনৰ পিপলছ লিবাৰেচন আৰ্মী (পিএলএ)-ৰ মাজত নতুনকৈ মুখামুখি হোৱাৰ দাবীক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। সামাজিক মাধ্যমত জুলাই মাহৰ ২৬ তাৰিখৰ বুলি দাবী কৰা কিছুমান ছবি আৰু ভিডিঅ' বিয়প পৰাৰ পিছতে এই বিষয়টোৱে নতুনকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে। অৱশ্যে, ঘটনাটোৰ চৰকাৰী নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও হোৱা নাই।

কিছুমান স্থানীয় সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে

সম্ভাব্য মুখামুখিৰ ঘটনা ২৫ জুলাইৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই এই দাবীসমূহৰ সত্যতা এতিয়াও নিশ্চিত কৰা নাই।

তাকচিং, মাজা, গেলেমু, পটৰাং হ্ৰদ, তামা চুচু, গেলেম সিনিক আৰু শ্ৰীচু উপত্যকাৰ দৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত চীনৰ সামৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। স্থানীয় নাহ ৰেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে পূৰ্বে অভিযোগ কৰিছিল যে স্থানীয় লোকসকলে পৰস্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি অহা চৰাইভূমি আৰু বনাঞ্চলত চীনে পথ, দলং আৰু সামৰিক শিবিৰ নিৰ্মাণ কৰিছে।

অৱশ্যে ভাৰতীয় সেনা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গৃহমন্ত্ৰী মামা নাটুঙে নতুনকৈ চীনা অনুপ্ৰৱেশৰ বাতৰি অস্বীকাৰ কৰি এইবোৰক

উৰাবাতৰি বুলি অভিহিত কৰিছে। চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ ব্যৱস্থাৰ সত্যতা পৰীক্ষা শাখাই ৬০ কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ পিএলএ আগবাঢ়ি অহাৰ দাবী কৰা এটা ভাইবেল ভিডিঅ'ও ভুৱা বুলি স্পষ্ট কৰিছিল।

নতুন ছবি আৰু ভিডিঅ'ক লৈ সৃষ্টি হোৱা অনিশ্চয়তাৰ মাজতে কামলে জিলাৰ এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি অজয় মুৰ্তেমে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন মুকলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ঘটনাস্থলীসমূহৰ মাটিত পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে।

তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়, ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰি দাবীসমূহৰ সত্যতা পৰীক্ষা

কৰাৰ লগতে বিষয়টো সন্দৰ্ভত চৰকাৰী বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা উদ্বেগ দূৰ কৰিবলৈ সীমান্ত নিৰাপত্তা আৰু নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ আস্থা বৃদ্ধিৰ বাবেও পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে।

বৰ্তমানলৈকে ভাইবেল ছবি-ভিডিঅ'বোৰৰ সত্যতা বা তাকচিং অঞ্চলত ভাৰত-চীন সেনাৰ কোনো নতুন মুখামুখি সংঘটিত হোৱাৰ কথা কৰ্তৃপক্ষই আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই। সেয়ে চৰকাৰী তথ্য প্ৰকাশ নোহোৱালৈকে দাবীসমূহক নিশ্চিত ঘটনা হিচাপে গণ্য নকৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে।

ডিচেম্বৰত বাংলাদেশলৈ উভতাৰ শপত শ্বেখ হাছিনাৰ

জন জন বিচাৰ ...৫ নতুন দিল্লী

বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত দেশলৈ উভতি যোৱাৰ ঘোষণা কৰি বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত নতুন চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ২০২৪ চনৰ ৫ আগষ্টত ব্যাপক ছাত্ৰ আন্দোলনৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰি ভাৰতলৈ অহাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে ভাৰতৰেডিয়ে কথো পাতি হাছিনাই এই ঘোষণা কৰে।

প্ৰায় ২৫ মিনিটৰ এই ভাষণত কেমেৰা বন্ধ ৰখা হৈছিল আৰু অডিঅ' সংযোগৰ জৰিয়তে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতে। ভাষণৰ সময়ত আৱেগিক হৈ পৰা হাছিনাই কয় যে বিগত দুটা বছৰত তেওঁ নিজৰ দেশৰ মানুহে বহু কষ্ট ভোগ কৰা দেখিছে। তেওঁৰ মতে, বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ সেই দেশ নহয়, যিখন দেশ গঢ়ি তোলাৰ বাবে ১৯৭১ চনত লাখ লাখ মানুহে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল।

‘জীৱন গ’লেও উভতি যাম’ হাছিনাই স্পষ্টভাৱে কয় যে তেওঁ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশলৈ উভতি যাব। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভুৱা গোচৰ, বিচাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া বা মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় থাকিলেও তেওঁ ভয় নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে। তেওঁৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰশ্ন উঠিছে-সঁচাকৈ যদি হাছিনা বাংলাদেশলৈ উভতি যায়, তেন্তে



তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আইনী ব্যৱস্থাৰ পৰিণতি কি হ'ব? তেওঁৰ ওপৰত দিয়া মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় কাৰ্যকৰী কৰাৰ চেষ্টা কৰা হ'বনে? নে নতুন ৰাজনৈতিক সমীকৰণে পৰিস্থিতি সলনি কৰিব?

বিশেষজ্ঞৰ মতে ‘অতি সাহসী সিদ্ধান্ত’

ভাৰতীয় প্ৰাক্তন সামৰিক বিষয়া তথা প্ৰতিৰক্ষা বিশ্লেষক লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অৱসৰপ্ৰাপ্ত জে এছ সোটাৰ মতে, হাছিনাৰ উভতি যোৱাৰ ঘোষণা এক অতি সাহসী ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ। তেওঁৰ মতে, বাংলাদেশলৈ উভতি গ'লে হাছিনাক গ্ৰেপ্তাৰ বা আন ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি তেওঁ নিজেও জানে।

বিশ্লেষকগৰাকীৰ মতে, এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতো দেশলৈ উভতি যোৱাৰ সিদ্ধান্তই বাংলাদেশৰ ৰাজনীতিত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। অৱশ্যে হাছিনাৰ ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে যিকোনো অনুমানৰ আগতে বাংলাদেশৰ আইনী আৰু ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ।

‘উচ্চশিক্ষাৰ লক্ষ্য কেৱল ডিগ্ৰী নহয় চিন্তাশীল আৰু দায়িত্বশীল নাগৰিক গঢ়া’

জন জন বিচাৰ ...৫ গুৱাহাটী

উচ্চশিক্ষাই কেৱল ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰাই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য নহয়; বৰং শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সমালোচনামূলক চিন্তা, মানৱীয়তা, দায়িত্ববোধ আৰু নেতৃত্ব গুণ বিকশিত কৰিব লাগে। এই মন্তব্য কৰিছে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লালদুহোমাই। গুৱাহাটীৰ দ্য আছাম ৰয়েল থ্ৰ'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত অনুষ্ঠিত ‘দীক্ষাৰত্ন-২০২৬’ শিক্ষাৰ্থী পৰিচয় কাৰ্যসূচীত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্য ভাষণ দি তেওঁ কয় যে বৰ্তমান দ্ৰুতগতিত

পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ যুৱ প্ৰজন্মক কেৱল পৰীক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাৰাখি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গীৰে গঢ়ি তুলিব লাগিব। লালদুহোমাই শিক্ষাৰ্থীসকলক “কি ভাবিব লাগে”ৰ সলনি “কেনেকৈ ভাবিব লাগে” সেই শিক্ষা লাভ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁৰ মতে, স্বাধীন বিচাৰ-বুদ্ধি, বৌদ্ধিক কৌতুহল আৰু যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তাধাৰাই ভৱিষ্যতৰ সুদক্ষ নেতৃত্ব গঢ়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে।

তেওঁ লগতে কয় যে

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ দায়িত্ব কেৱল শৈক্ষিক জ্ঞান প্ৰদান কৰাত সীমাবদ্ধ নহয়। শিক্ষামুঠানসমূহে শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সহানুভূতি, সামাজিক দায়িত্ববোধ, দূৰদৰ্শিতা আৰু সমাজৰ প্ৰতি কৰ্তব্যবোধ গঢ়ি তুলিব লাগে।

মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক শ্ৰেণীকোঠা আৰু পৰীক্ষাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি শিক্ষক জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। তেওঁ কয় যে জ্ঞানৰ সৈতে মূল্যবোধ আৰু নেতৃত্ব গুণৰ সমন্বয় ঘটিলেহে যুৱ প্ৰজন্মই সমাজত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হ'ব।

অসমত ৰন্ধন গেছ গ্ৰাহকলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশ

জন জন বিচাৰ ...৫ গুৱাহাটী

অসমত ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহকসকলক ১৬ আগষ্টৰ ভিতৰত আধাৰভিত্তিক বেদুতিনি গ্ৰাহক পৰিচয় যাচাই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত এই পৰিচয় যাচাই সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছৰ চিলিঙৰ লাভৰ সুবিধা হেৰুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে।

ৰাজহুৱা খণ্ডৰ তেল বিপণন সংস্থাসমূহে গ্ৰাহকৰ পৰিচয় যাচাইৰ বাবে ১৬ আগষ্টক অন্তিম সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। সময়মতে পৰিচয় যাচাই নকৰা গ্ৰাহকে ভৱিষ্যতে ৰাজসাহায্যবিহীন বা অধিক মূল্যত ৰন্ধন গেছৰ চিলিঙৰ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। গ্ৰাহকসকলে নিজ নিজ অনুমোদিত ৰন্ধন গেছ

বিতৰকৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ আধাৰ নম্বৰ আৰু গ্ৰাহক সংযোগৰ তথ্য প্ৰদান কৰি পৰিচয় যাচাই সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি সংশ্লিষ্ট সংস্থাৰ অনুমোদিত ম'বাইল এপৰ জৰিয়তেও আঙুলিৰ ছাপ বা মুখমণ্ডল চিনাক্তকৰণৰ মাধ্যমেৰে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। এই দেশজোৰা পৰিচয় যাচাই অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভুৱা আৰু একাধিক ৰন্ধন গেছ সংযোগ চিনাক্ত কৰি বন্ধ কৰা আৰু চৰকাৰী ৰাজসাহায্য যাতে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ হাততহে উপনীত হয়, সেয়া নিশ্চিত কৰা।

গেছ বিতৰকসকলে গ্ৰাহকসকলক অন্তিম দিনলৈ অপেক্ষা নকৰি আগতীয়াকৈ পৰিচয় যাচাই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। সময়মতে প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰন্ধন গেছৰ যোগান অব্যাহত ৰখাত কোনো অসুবিধা নহ'ব।

অৰুণাচলৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পাহাৰ খহি অসমৰ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু

ইটানগৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৰুং কুমে জিলাৰ পাৰ্চি পালৌ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত পাহাৰ খহি অহাৰ ফলত অসমৰ এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু আন এজন শ্ৰমিক আহত হয়। এই ঘটনাত পাহাৰৰ পৰা মাটি, শিল আৰু বৃহৎ শিলাখণ্ড খহি প্ৰকল্পস্থলীত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত পৰে।

দুৰ্ঘটনাত নিহত শ্ৰমিকজনক ধেমাজি জিলাৰ নিবাসী নবীন দলে বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। পাহাৰৰ পৰা খহি অহা মাটি আৰু শিলৰ তলত পুতি যোৱাৰ ফলত ঘটনাস্থলীতে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে। ঘটনাৰ পিছতে উদ্ধাৰ অভিযান

চলাই আন এজন শ্ৰমিকক মাটি-শিলৰ মাজৰ পৰা জীবন্তে উদ্ধাৰ কৰা হয়। আহত শ্ৰমিকজনক তাৎক্ষণিক চিকিৎসাৰ বাবে ওচৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। অৱশ্যে বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে আহত শ্ৰমিকজনৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিব পৰা হোৱা নাই।

কুৰুং কুমে জিলাৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া মতে, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰকল্প পৰিচালনাই ক্ষতিগ্ৰস্ত স্থানৰ বিস্তৃত পৰ্যবেক্ষণ আৰু মূল্যায়ন আৰম্ভ কৰিছে। ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে।

বানপানীৰ কাৰণ পৰীক্ষা কৰিব মেঘালয় চৰকাৰে

শ্বিলং : অসম-মেঘালয় আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্তৰ যোৰাবাটত সঘনাই দেখা দিয়া বানপানী আৰু জলাবদ্ধতাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ মেঘালয় চৰকাৰে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৱাড কে. ছাংমাই কয় যে অঞ্চলটোত চলি থকা পথ নিৰ্মাণৰ কামো বানপানীৰ অন্যতম কাৰণ হ'ব পাৰে। ভাৰী বৰষুণৰ সময়ত যোৰাবাটত বাৰে বাৰে পানী জমা হৈ যাতায়াত ব্যাহত হৈ আহিছে। ইয়াৰ ফলত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত দৈনিক অহা-যোৱা কৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰে স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত বানপানীৰ সকলো সম্ভাৱ্য কাৰণ পৰীক্ষা কৰি আছে। জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলেও ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰি তাৎক্ষণিক আৰু

দীৰ্ঘম্যাদী সমাধানৰ পথ বিচাৰি আছে।

ছাংমাইৰ মতে, যোৰাবাটত চলি থকা পথ নিৰ্মাণৰ ফলত মূল উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ ভূমি যথেষ্ট তললৈ নামি গৈছে। সেই স্থানত পানী জমা হোৱাৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰতে বানপানী সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।

অৱশ্যে কেৱল পথ নিৰ্মাণেই ইয়াৰ কাৰণ নেকি, সেই বিষয়ে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জলাবদ্ধতাৰ আঁৰত আন কিছুমান কাৰকো থাকিব পাৰে আৰু সেইবোৰো পৰীক্ষা কৰা হ'ব।

তেওঁ কয়, “বাইজৰ অসুবিধা কমোৱাটো চৰকাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰি সমস্যাটো স্থায়ীভাৱে হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।”

‘পৰমার্থম’ গোটৰ বানাক্ৰান্তলৈ দ্বিতীয়টো সহায়ৰ হাত

জন জন বিচাৰ

...৫ গুৱাহাটী

উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ কাষত পুনৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে জনপ্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক মঞ্চ ‘পৰমার্থম’-এ। গোটটোৰ অসমৰ মুখ্য প্ৰশাসক জোন বৰাৰ নেতৃত্বত সদস্যসকলে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ সমভাণী হয় আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে।

এই সাহায্য অভিযানত জ্যোতিকৃষ্ণৰ ‘কল্যাণী আত্মসহায়ক



গোটৰ মহিলাসকলেও সহযোগিতা আগবঢ়ায়। বানাক্ৰান্ত প্ৰায় ১০০টা পৰিয়ালৰ মাজত ব্লিচি পাউডাৰ,

ফেনাইল, ডেটল, বহী, কলম, পেঞ্চিল, ফৰী, আইনাৰ লগতে সেন্দূৰ, তেল, ছাতি, শিশুৰ নতুন

কাপোৰ, ডাঙৰ বেগ, চেণ্ডেল আদি বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হয় উল্লেখ্য যে বানৰ ফলত বহু পৰিয়ালে দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱত ভুগি থকাৰ সময়তে ‘পৰমার্থম’ৰ এই উদ্যোগে বানাক্ৰান্ত লোকসকলক কিছু সহায় প্ৰদান কৰিছে। সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত এটা মঞ্চই সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ অংশ হিচাপে আগবঢ়োৱা এই পদক্ষেপে মানৱীয় সহমতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে।

সাহায্য অভিযানত গোটটোৰ বিত্ত সম্পাদক মিনাক্ষী বৰা, প্ৰণৱ জ্যোতি বৰদলৈ, যতীন কুমাৰ গগৈ, ৰাতুল গোহাঁই, বিৰিঞ্চি গোহাঁই আদিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে।

আন্তঃপ্ৰতিষ্ঠান চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা সম্পন্ন

জন জন বিচাৰ

...৫ গুৱাহাটী

গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণু-নিৰ্মলা ভৱন, লতাশিলত ২৬ জুলাইত ৩০সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া-সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ আন্তঃপ্ৰতিষ্ঠান চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা সফলতাবে অনুষ্ঠিত হয়। অসম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচন, অসম ছ'চি'অ'-কালচাৰেল এছ'চিয়েচন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া-সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ আয়োজক সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাতখন উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত আধুনিক, প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰসাৰৰ পথপ্ৰদৰ্শক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী, অভিনেতা তথা ক্ৰীড়াবিদ ক্ৰীড়াৰত্ন লৌহপুৰুষ প্ৰমোদ কান্ত শৰ্মাৰ ১১সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজন কৰা হয়।

প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানৰ শতাধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল দুগৰাকী



বিশিষ্ট চিত্ৰশিক্ষক অথিলাভ দত্ত আৰু নীলাঞ্জন দাসে পৰীক্ষা কৰে।

পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া-সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ প্ৰতিযোগিতা সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰাজীৱ প্ৰকাশ বৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰে। অনুষ্ঠানত অসম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ক্ৰীড়াবিদ কৈলাশ শৰ্মা, অসম ছেপাক টাৰ্ক এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক বিষ্ণুৰাম নুনুছা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা নৰ্থ-ইষ্ট কেঙ্গাৰ হাস্পাতালৰ অধ্যক্ষ গণেশ তামুলী, মহোৎসৱৰ সম্পাদক

অমৰ কাশ্যপ, ৰাষ্ট্ৰীয় চাইকেল আৰোহী দ্বিবা কাশ্যপ, উপ-সভাপতি নাছিকুদ্দিন খান চৌধুৰী, নগাঁওৰ এমটিঅ' দীনেশ চন্দ্ৰ ডেকা, অসম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদক গীতু দাস, অমল মেধি আৰু জিতেন শৰ্মাই উপস্থিত থাকি প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰে। অনুষ্ঠানটো মানস শৰ্মাই পৰিচালনা কৰে। আয়োজকসকলে কয় যে এনে প্ৰতিযোগিতাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা বিকাশৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত সুন্দৰ সময়ৰ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব।

এই সপ্তাহৰ বাৰ্শিফল

৭ আগষ্ট, ২০২৬ৰ পৰা ১৩ আগষ্ট, ২০২৬লৈ

মেঘ : অদৰ্কাৰী সাহস পৰাক্ৰম প্ৰদৰ্শনৰ পৰা বিৰত থাকক। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা সফল লাভ। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে।

বৃষ : চেপ্তা সাহস পৰাক্ৰম বৃদ্ধি। বৈদেশিক কৰ্মৰ লগত জৰিত ক্ষেত্ৰৰ পৰা ধন লাভ। ভাগ্যৰ সহায় লাভ।

মিথুন : অৰ্থিক ক্ষেত্ৰত শুভ ফল লাভ। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি। অদৰ্কাৰী কথাত প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বিৰত থাকক।

কৰ্কট : অদৰ্কাৰী আত্মবিশ্বাসৰ ফলত মানসিক অশান্তি আহিব পাৰে। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ থাকিব।

সিংহ : কৰ্মক্ষেত্ৰত অস্থিৰতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। সাফল্য লাভৰ ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমিত হ'ব পাৰে। অৰ্থব্যয় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে।

কন্যা : ভাগ্যৰ সহায় লাভ। কৰ্মক্ষেত্ৰত অদৰ্কাৰী বাদ বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি।

তুলা : কৰ্মক্ষেত্ৰত অস্থিৰতা বৃদ্ধি। অদৰ্কাৰী বাদ বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ থাকিব।

বৃশ্চিক : মানসিক অস্থিৰতা থাকিব। পিতৃৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সচেতন হওক। দৈনন্দিন কাৰ্য্য কলাপ ত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি।

ধনু : বিপৰীত পৰিস্থিতিৰ পৰা লাভ। অদৰ্কাৰী বাদ বিবাদৰ পৰা বিৰত থাকক। পতি - পত্নীৰ মাজত মনোমালিন্য হ'ব পাৰে।

মকৰ : ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ। নিত্য নৈমন্তিকবাৰ্তা বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। চেপ্তাৰ সফলতা লাভ।

কুন্ত : কৰ্মদক্ষতাৰ সুনাম বৃদ্ধি। প্ৰতিযোগিতা মূলক কাৰ্য্যত সফলতা অৰ্জন। মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে।

মীন : চেপ্তাৰ সফলতা থাকিব। বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে সপ্তাহটো শুভ। আকস্মিক অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা আছে।

-হিতেন শৰ্মা শাস্ত্ৰী

অধ্যাপক, বিশ্ব জ্যোতিষ বিদ্যাপীঠ, অসম শাখা

যোগাযোগ : ৯৮৫৪০২৬৭৭৯

চৰকাৰী চাকৰিত দুৰ্নীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব: হিমন্ত বিশ্ব

জন জন বিচাৰ
...গুৱাহাটী

অসমত চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া দুৰ্নীতিমুক্ত আৰু আগন্তুক পাঁচ বছৰতো নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হ'বলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দৃঢ় ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰে।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰা হৈছে। এই ব্যৱস্থা আগন্তুক পাঁচ বছৰতো অটুট ৰখাৰ বাবে চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশ্বাস দিয়ে।

বানপীড়িত শিক্ষানুষ্ঠানলৈ
২ লাখকৈ

শেহতীয়া বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৰাজ্যৰ ৭৯৩খন শিক্ষানুষ্ঠানলৈ এককালীন ২ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বানৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু শৈক্ষিক পৰিৱেশ স্বাভাৱিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সাহায্যই



সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

‘বাবু আছনি’ত বৃদ্ধি মাহিলী সহায় শিক্ষাৰ্থীসকলক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে ‘বাবু আছনি’ আঁচনিৰ অধীনত আৰ্থিক সাহায্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নতুন নিৰিখ অনুসৰি ডিগ্ৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে মাহে ১,০০০ টকা আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে মাহে ১,২০০ টকা লাভ কৰিব।

আনহাতে, ‘নিজুত মইনা’ আঁচনিৰ অধীনতে ছাত্ৰীসকলৰ মাহিলী সহায় বৃদ্ধি কৰা হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে মাহে ৮০০ টকা, স্নাতক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে ১,২০০ টকা আৰু

স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰীয়ে ২,৫০০ টকা লাভ কৰিব।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই পদক্ষেপসমূহৰ মূল লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ সুযোগ অধিক শক্তিশালী কৰা, আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীক সহায় কৰা আৰু বানপানীৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মাজতো ৰাজ্যৰ শিক্ষাব্যৱস্থা অব্যাহত ৰখা।

চাকৰিত স্বচ্ছতা আৰু শিক্ষাত সহায়-দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰৰ এই নতুন ঘোষণাই আগন্তুক দিনত ৰাজ্যৰ যুৱসমাজ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে।

দোষাৰোপ নহয়, সমূহীয়া পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন

অসমৰ বানক লৈ নাগালেণ্ডৰ মন্ত্ৰী

ক'হিমা : অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা অভিযোগ-প্ৰত্যাৰোপৰ মাজতে নাগালেণ্ডৰ পৰ্যটন আৰু উচ্চ শিক্ষা মন্ত্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙে দুয়োখন ৰাজ্যক পৰস্পৰক দোষাৰোপ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সমূহীয়াভাৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শেহতীয়া ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বানত অসম আৰু নাগালেণ্ড দুয়োখন ৰাজ্যই ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে। সেয়েহে এনে সংকটৰ সময়ত পৰস্পৰক দোষ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক সহায় কৰাত গুৰুত্ব দিব লাগে।

উল্লেখ্য, অসমৰ উজনি জিলাসমূহত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ সৈতে নাগালেণ্ডত চলি থকা অবৈধ খনিজ সম্পদ আহৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ সম্ভাৱ্য সম্পৰ্কক লৈ বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল। এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত আলঙে কয় যে নাগালেণ্ড চৰকাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্থাপন কৰা বিষয়সমূহ গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত বিষয়টো সন্দৰ্ভত যোগাযোগ চলি আছে।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শেহতীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত নাগালেণ্ডতো পাহাৰ খহি যোৱা, দলং উটি যোৱা, ঘৰ-দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা, মানুহৰ মৃত্যু আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ দৰে ব্যাপক ক্ষতি হৈছে।

তেওঁ কয়, “আমি ইজনে-সিজনক কোনো কথাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি সমূহীয়াভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব।” বিষয়টো নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকতো আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে।

নাগালেণ্ডৰ কন্যাক ইউনিয়নকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনে মন জিলাত অবৈধ খননৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিসকলক দায়িত্বশীল মন্তব্য কৰিবলৈ আহ্বান জনায়।

তেওঁ কয় যে অসম আৰু নাগালেণ্ডৰ জনসাধাৰণৰ মাজত ভুল বুজাবুজি বা উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিব পৰা মন্তব্যৰ পৰা সকলো পক্ষই আঁতৰি থাকিব লাগে। দুয়োখন ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণৰ দুখ-কষ্ট লাঘৱ কৰাটোৱেই এই সময়ত মূল লক্ষ্য হোৱা উচিত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে।

পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত আলঙে কয় যে নাগালেণ্ড চৰকাৰে বনানীকৰণ আৰু জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যগুৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে।

হাইলাকান্দি নাবালিকাৰ ধৰ্ষণ-হত্যা গোচৰৰ ৰহস্য ভেদ

হাইলাকান্দি : হাইলাকান্দিৰ আলাইছৰা অঞ্চলত ১৬ বছৰীয়া এগৰাকী নাবালিকাৰ ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অভিযোগে সমগ্ৰ জিলাখনক জোকাৰি যোৱাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে মাত্ৰ ৭২ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোচৰটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ উদঘাটন কৰাৰ দাবী কৰিছে। আৰক্ষীৰ মতে, ঘটনাটোৰ আঁৰত থকা সম্ভাৱ্য কাৰণ হিচাপে এটা ত্ৰিকোণীয়া সম্পৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা বিবাদৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে গোচৰটোৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হোৱা পাঁচজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এজন কিশোৰ সন্দেহযুক্তক আটক কৰি কিশোৰ গৃহত ৰখা হৈছে।

সংবাদমেলত হাইলাকান্দিৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহাই কয় যে গোচৰটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিগত তথ্য, ম'বাইল ফোনৰ কল ৰেকৰ্ড, ডিজিটেল তথ্য,

ফৰেনছিক পৰীক্ষা আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে।

আৰক্ষীৰ মতে, আপু মালাকাৰ আৰু মনোজ দাস ওৰফে ৰাজদীপক ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। আনহাতে, বীৰাজ দাস, প্ৰসেনজিৎ ওৰফে পিংকু আৰু জয়দীপে অপৰাধটো সংঘটিত কৰাত সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে বৰ্তমানলৈ সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণৰ ভিত্তিত পাঁচজনৰ বিৰুদ্ধে ঘটনাটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্কৰ যথেষ্ট তথ্য লাভ কৰা হৈছে।

আৰক্ষীৰ তদন্ত অনুসৰি, ১ আগষ্টৰ নিশা অভিযুক্তসকল আলাইছৰাত থকা কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ গৈছিল বুলি অভিযোগ। আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা মতে, তাত যৌন নিৰ্যাতন সংঘটিত কৰাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীক হত্যা কৰা হয়।

IND 365 অসমne

ৰবাবে

নগাঁও, জাগীৰোড, হোজাই

লংকা, কঠিয়াতলি, কামপুৰ

বৰপেটা, নলবাৰী

ৰ পৰা সংবাদদাতা বিচৰা হৈছে

IND 365

দৈনিক অসম

সম্পাদকীয় উজ্জ্বল ভারত ক্ৰীড়াৰ ভৱিষ্যৎ

গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ সফলতাই দেশৰ ক্ৰীড়া জগতত নতুন আশাৰ সঞ্চার কৰিছে। প্রতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ বাবে ছটা স্বৰ্ণসহ ৩১টা পদকৰ অনুমান কৰা হৈছিল। কিন্তু খেলুৱৈসকলে সেই অনুমান অতিক্রম কৰি ১৩টা স্বৰ্ণ, ১৭টা ৰূপ আৰু ৯টা বৰ্জসহ মুঠ ৩৯টা পদক লাভ কৰি নিজৰ সামৰ্থ্য প্ৰমাণ কৰিলে।

এই সফলতাৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশ

হৈছে সীমিত খেল আৰু সৰু দলৰ মাজতো ভাৰতৰ উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন। বক্সিঙত বিশেষভাৱে ভাৰতৰ আধিপত্য দেখা গ'ল। ১৪জনীয়া দলৰ ১০জন খেলুৱৈয়ে পদক লাভ কৰাটো নিঃসন্দেহে প্ৰশংসনীয়। জুডোত ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰাও এক ঐতিহাসিক কৃতিত্ব। ভাৰোত্তোলনত মীৰাবাই চানুৰ স্বৰ্ণজয় আৰু এথলেটিকছত নীৰজ চোপ্ৰা, গুলভীৰ সিং, তেজস্বিন শংকৰ আদিৰ সফলতাই ভাৰতীয় ক্ৰীড়াৰ গভীৰতা স্পষ্ট কৰিছে।

ভাৰতৰ এই অগ্ৰগতিৰ আঁৰত উন্নত ক্ৰীড়া পৰিকাঠামো, প্ৰশিক্ষণ, আৰ্থিক সহায় আৰু প্ৰতিভা অন্বেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ ভূমিকা আছে। 'খেলো ইণ্ডিয়া' আৰু 'টাগেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কীম'ৰ দৰে আঁচনিয়ে গ্ৰামাঞ্চল আৰু

সৰু চহৰৰ প্ৰতিভাক আঙুৰাই অহাৰ সুযোগ দিছে।

অৱশ্যে কমনৱেলথৰ সফলতাতোই সন্তুষ্ট হৈ থাকিলে নহ'ব। আগন্তুক এচিয়ান গেমছ আৰু অলিম্পিকত অধিক কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। সেয়েহে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰশিক্ষণ, ক্ৰীড়া বিজ্ঞান, পুষ্টি আৰু মানসিক প্ৰস্তুতিত অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব।

বিদেশৰ মাটিত ত্ৰিৰংগা উৰিলে আৰু 'জন গণ মন' ধ্বনিত হ'লে সেয়া কেৱল এজন খেলুৱৈৰ বিজয় নহয়-সমগ্ৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ। গ্লাছগোৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰিছে, সচিক পৰিকল্পনা আৰু নিৰন্তৰ পৰিশ্ৰম অব্যাহত থাকিলে ভাৰতৰ ক্ৰীড়াৰ ভৱিষ্যৎ নিশ্চয়েই উজ্জ্বল।

স্বচ্ছ ভাৰতৰ সপোন কিয় এতিয়াও আধৰুৱা ?

জন জন বিচার
...গুৱাহাটী

এখন পৰিষ্কাৰ, সুস্থ আৰু আধুনিক ভাৰতৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে 'স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান'। চহৰৰ ৰাজপথ, বজাৰ, ৰেল ষ্টেচন আৰু ৰাজহুৱা স্থান পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু এই চকুত পৰা স্বচ্ছতাৰ আঁৰত লুকাই আছে আন এক কঠোৰ বাস্তৱতা-নলা-নৰ্দমা আৰু চেপ্টিক টেংক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নামি বহু শ্ৰমিকৰ প্ৰাণ গৈ আছে।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সসৈদত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০১৭ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ১৭ মাৰ্চলৈ দেশত নলা আৰু চেপ্টিক টেংকৰ হাতেকামৰ পৰিষ্কাৰৰ সময়ত বিযুক্ত গেছত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ ৬২২জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। কেৱল দিল্লীতে এই সময়ছোৱাত ৬২জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চৰকাৰী তথ্যত উল্লেখ কৰা হৈছে। এই পৰিসংখ্যাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে-যি পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ বাবে অভিযান চলিছে, সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনৰ মূল্য কিমান?

অহিনা আছে, নিৰাপত্তা ক'ত?

নিয়ম অনুসৰি, পৰাপ্ত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অবিহনে কোনো শ্ৰমিকক নলা বা চেপ্টিক টেংকৰ ভিতৰত নমোৱা নিষিদ্ধ। বিশেষ পৰিস্থিতিত ভিতৰলৈ যোৱাটো অত্যাৱশ্যক হ'লে বিযুক্ত গেছ আৰু অক্সিজেনৰ মাত্ৰা পৰীক্ষা কৰা, হেলমেট, সুৰক্ষা পোছাক, হাতমোজা, গামবুট, সুৰক্ষা হাৰ্নেছ, গেছডিটেক্টৰ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ সঁজুলি যোগান ধৰাটো বাধ্যতামূলক।

ইয়াৰ উপৰি ঘটনাস্থলীত প্ৰশিক্ষিত উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থাও থাকিব লাগে। উচ্চতম ন্যায়ালয়েও নলা আৰু চেপ্টিক টেংকৰ পৰিষ্কাৰ কাম সুৰক্ষিত আৰু অধিকাংশ ক্ষেত্ৰত যান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সম্পন্ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।

তথাপি বাস্তৱৰ ছবিখন বহু ক্ষেত্ৰত বেলেগ। যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'লেও কেতিয়াবা কেৱল ওপৰৰ তৰল অৱজ্ঞান আঁতৰোৱা হয়। তলত জমা হোৱা বোকা বা কটন আৱৰ্ত্তন আঁতৰাবলৈ পুনৰ শ্ৰমিকক টেংকৰ ভিতৰত নমোৱা হয়।



ফলত আধুনিক যন্ত্ৰ থাকিলেও পুৰণি বিপজ্জনক পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱা নাই।

বিযুক্ত গেছেই হৈ পৰে মৃত্যুৰ ফান্দ

নলা আৰু চেপ্টিক টেংকৰ ভিতৰত সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশ অতি বিপজ্জনক। তাত হাইড্ৰ'জেন ছালফাইড, মিথেন, কাৰ্বন মন'ক্সাইড, কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু এম'নিয়াৰ দৰে বিযুক্ত গেছ থাকিব পাৰে। এই গেছৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পালে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা দ্ৰুতভাৱে কমি যায়।

বিশেষকৈ হাইড্ৰ'জেন ছালফাইড অত্যন্ত বিপজ্জনক। অধিক ঘনত্বত এই গেছৰ মাত্ৰ কেইটামান শ্বাসেই এজন মানুহক অচেতন কৰি পেলাব পাৰে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মৃত্যু ঘটাব পাৰে। অৰ্থাৎ নলা বা চেপ্টিক টেংকৰ ভিতৰত নামি যোৱা এজন শ্ৰমিকৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত্তই জীৱন-মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত।

মুন্ডকাৰ ঘটনাই পুনৰ দেখুৱালে কঠোৰ বাস্তৱ

২০২৬ চনৰ ২৬ জুনত পশ্চিম দিল্লীৰ মুন্ডকা ঔদ্যোগিক এলেকাত সংঘটিত এক ঘটনাই এই সমস্যাটোক পুনৰ দেশৰ সন্মুখলৈ আনিছিল। চেপ্টিক টেংক পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ গৈ অৰুণ, চান্দ আৰু সন্দীপ নামৰ তিনিজন শ্ৰমিকৰ বিযুক্ত গেছত শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যু হয়। প্ৰাথমিক তদন্ত অনুসৰি, প্ৰথমজন শ্ৰমিক টেংকৰ ভিতৰত নামিছিল। তেওঁৰ কোনো

সঁহাৰি নোপোৱাত আন এজনেও উদ্ধাৰৰ উদ্দেশ্যে ভিতৰলৈ নামিছিল। কিছু সময়ৰ পিছত তৃতীয়জনো সেই একে বিপজ্জনক পৰিৱেশৰ বলি হয়। উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা লোকেও একে বিযুক্ত গেছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহি মৃত্যুমুখত পৰে।

এই ঘটনাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে-প্ৰশিক্ষণ, গেছ পৰীক্ষা, সুৰক্ষা সঁজুলি আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল অবিহনে চেপ্টিক টেংকৰ ভিতৰত নামা মানে কেৱল এজন শ্ৰমিকক নহয়, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা আন এজন ব্যক্তিকো মৃত্যুৰ মুখলৈ টেলি দিয়া।

**জাত-পাতৰ ৰোজা আজিও
কঢ়িয়াইছে শ্ৰমিকসকলে**

ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ বহু দশক পাৰ হৈ গ'লেও পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ দৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কামৰ সৈতে এতিয়াও এটা নিৰ্দিষ্ট সামাজিক গোটিৰ নাম জড়িত হৈ আছে। জাতিগত বৈষম্য আৰু সামাজিক অৱহেলাৰ ইতিহাসে এই শ্ৰমিকসকলৰ জীৱনক অধিক কঠিন কৰি তুলিছে। মহাত্মা গান্ধীয়ে পৰিষ্কাৰকৰ্মীসকলৰ বসতিত সময় কটাই তেওঁলোকৰ সামাজিক অৱস্থাৰ প্ৰতি সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল। তেওঁ নিজে নিজৰ মল-মূত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। ডঃ

ভীমৰাও আম্বেদকৰেও জাতিগত ব্যৱস্থাৰ বাবে জন্মৰ পৰাই কোনো ব্যক্তিক পৰিষ্কাৰকৰ্মীৰ কামত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ প্ৰথাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল।

আজিও বহু পৰিষ্কাৰকৰ্মী স্থায়ী কৰ্মচাৰী নহয়; তেওঁলোকৰ একাংশ চুক্তিভিত্তিক বা দৈনিক মজুৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। ফলত নিজৰ জীৱন বিপন্ন কৰা কামৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰাপত্তাৰ দাবী উত্থাপন কৰাৰ ক্ষমতা বহু সময়ত সীমিত হৈ পৰে।

যান্ত্ৰিকীকৰণেই হ'ব পাৰে সমাধান

হাতেকামৰ পৰিষ্কাৰ পদ্ধতি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি অধিক যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো সময়ৰ দাবী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হাতেকামৰ মল পৰিষ্কাৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ পৰিসৰৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। চহৰ আৰু বৃহৎ গাঁও পঞ্চায়তসমূহত আধুনিক পৰিষ্কাৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু কেৱল যন্ত্ৰ ক্ৰয় কৰিলেই সমস্যাৰ সমাধান নহ'ব। যন্ত্ৰৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণ, শ্ৰমিকৰ প্ৰশিক্ষণ, সুৰক্ষা সঁজুলি আৰু নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা-এই সকলোবোৰ একেলগে নিশ্চিত কৰিব লাগিব।

স্বচ্ছ ভাৰত তেতিয়াহে সফল হ'ব

স্বচ্ছ ভাৰতৰ অৰ্থ কেৱল ৰাস্তাত অৱজ্ঞান নথকা বা চহৰৰ দেৱাল পৰিষ্কাৰ হৈ থকাই নহয়। যিজন শ্ৰমিকে আমাৰ নলা, চেপ্টিক টেংক আৰু নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰি সমাজক সুস্থ আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, তেওঁৰ জীৱন যদি সুৰক্ষিত নহয়, তেন্তে সেই স্বচ্ছতাৰ দাবী সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে।

সেয়ে এতিয়া প্ৰয়োজন 'স্বচ্ছতা'ৰ সংজ্ঞা নতুনকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ। পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ লগতে পৰিষ্কাৰকৰ্মীৰ সুৰক্ষা, সম্মান, ন্যায্য মজুৰি আৰু মানৱ অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিব লাগিব। এজন শ্ৰমিক নলা বা চেপ্টিক টেংকৰ ভিতৰত নামি মৃত্যুবৰণ কৰাৰ প্ৰতিটো ঘটনা কেৱল এটা দুৰ্ঘটনা নহয়; ই প্ৰশাসনিক গাফিলতি, সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ব্যৰ্থতা আৰু সামাজিক বৈষম্যৰে প্ৰতিচ্ছবি।

স্বচ্ছ ভাৰতৰ প্ৰকৃত সাফল্য তেতিয়াহে আহিব, যেতিয়া দেশখন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দায়িত্ব লোৱা কোনো শ্ৰমিকেই নিজৰ জীৱনক পণ কৰি কাম কৰিবলগীয়া নহ'ব।

অকাল মৃত্যু অতিক আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ

জন জন বিচাৰ

...ৰাঁসি

কুখ্যাত মাফিয়া অতিক আহমেদৰ পৰিয়ালক লৈ ৰাঁসীত পুনৰ এক চাপ্ৰল্যাকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ৰাঁসি-কানপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত অতিক আহমেদৰ আটাইতকৈ সৰু পুত্ৰ আবান আহমেদ আৰু তেওঁৰ সংগী আহজম ওৰফে সেনুৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় পূছ থানাৰ অন্তৰ্গত খিল্লী গাঁৱৰ সমীপত। এই ঘটনাত গাড়ীখনত থকা আন তিনিজন লোকো গুৰুতৰভাৱে আহত হয়।

প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি, আবান আহমেদে ৰাঁসি জেলত বন্দী হৈ থকা তেওঁৰ ককায়েক আলী আহমেদক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ প্ৰয়াগৰাজৰ পৰা ৰাঁসিলৈ গৈ আছিল। সেই সময়তে তীব্ৰ বেগত অহা ট্ৰেণ্টা গাড়ীখন হঠাৎ নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পথৰ ভিত্তিৰে ভাঙি খুন্দা মাৰে। খুন্দাটো ইমানেই ভয়ংকৰ আছিল যে গাড়ীখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰে।

স্থানীয় লোকসকলে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত



‘হৃদয়ো আছে, অস্ত্ৰও আছে’-ভাবুকিমূলক গানৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেলৰ পিছত আবানৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ

প্ৰয়াগৰাজ: অতিক আহমেদৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আবান আহমেদৰ জীৱনৰ অন্ত পৰিল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত। আবান ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যাপক চৰ্চালৈ আহিছিল। এটা বিবাহ অনুষ্ঠানত তেওঁৰ উপস্থিতিৰ ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈছিল। ভিডিঅ’টোৰ পটভূমিত বাজি থকা এটা ভাবুকিমূলক গানক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। গানটোত অস্ত্ৰ আৰু শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ ভাবুকিমূলক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল।

এই ভিডিঅ’ক কেন্দ্ৰ কৰি ধূমগন্ধা থানাৰ আবানৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। এইটোৱেই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা প্ৰথম গোচৰ বুলি প্ৰতিবেদনত

উল্লেখ কৰা হৈছে।

অতিক আহমেদৰ পাঁচ পুত্ৰৰ ভিতৰত আবান আছিল কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ উমৰ আৰু দ্বিতীয় পুত্ৰ আলী জেলত বন্দী হৈ আছে। তৃতীয় পুত্ৰ আসাদ আহমেদ ২০২৩ চনৰ এপ্ৰিলত ৰাঁসীত আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল। আসাদ উমেশ পাল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত আছিল। এতিয়া ভাতৃ আলীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতেই ৰাঁসীত পথ দুৰ্ঘটনাত আবানৰ মৃত্যুৰে অতিক আহমেদৰ পৰিয়ালক পুনৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছে। আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাটোৰ কাৰণ অনুসন্ধান কৰি আছে। প্ৰাথমিকভাৱে গাড়ীৰ অত্যধিক গতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে।

হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলায় আৰু আহতসকলক পূছ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ লৈ যায়। চিকিৎসকে তাত দুজনক মৃত ঘোষণা কৰে। আৰক্ষীয়ে মৃত দুজনৰ ভিতৰত আবান আহমেদ আৰু আহজমৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিছে। আহতসকলৰ ভিতৰত মহম্মদ জাইদ, উমৰসহ আন লোক আছে।

ৰাঁসিৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক বি বি জি টি এছ মূৰ্ত্তিয়ে ঘটনাটো নিশ্চিত কৰি কয় যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলি আছে। প্ৰাথমিক তদন্তত গাড়ীৰ অত্যধিক গতি আৰু নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ পাইছে।

উল্লেখযোগ্য যে অতিক আহমেদৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ৰাঁসিৰ সম্পৰ্কিত এয়া তৃতীয়টো ডাঙৰ ঘটনা। ২০২৩ চনৰ ১৩ এপ্ৰিলত অতিকৰ পুত্ৰ আসাদ আহমেদ ৰাঁসিৰ বড়াগাও থানা এলেকাৰ পৰিছা নাহৰৰ সমীপত আৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত অতিকৰ আন পুত্ৰ আলী আহমেদক ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰত নৈনী জেলৰ পৰা ৰাঁসি জেললৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া সেই ভাতৃক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ যাওঁতেই আবানৰ মৃত্যুৰ ঘটনাই ৰাঁসীত পুনৰ অতিক আহমেদৰ পৰিয়ালক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰলৈ আনিছে।

বৃদ্ধাশ্ৰমত পিতৃৰ মৃত্যু, ভিডিঅ’ কলত শেষকৃত্য চালে কন্যা

জন জন বিচাৰ

...সোণিপত

সন্তানেই বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ-মাতৃৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আশ্ৰয়-এই ধাৰণাটো ভাৰতীয় সমাজত বহু পুৰণি। কিন্তু সলনি হোৱা জীৱনশৈলী, ব্যস্ততা আৰু দূৰত্বৰ মাজত বহু বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃয়ে এতিয়া নিঃসংগ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে। হাৰিয়ানাৰ সোণিপতৰ এটা ঘটনাই এই কঠিন বাস্তৱতকৈ পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে।

সোণিপতৰ সমাজ কল্যাণ শিক্ষা সমিতিৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত বাস কৰা শিৱচৰণ ৰামৰতন গুপ্তাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ কন্যাসকল অন্তৰ্বেষ্টিক্ৰিয়াত উপস্থিত নহ'ল। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ৫১০০ টকা পঠিয়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰে আৰু ‘ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে পিতৃৰ শেষকৃত্য প্ৰত্যক্ষ কৰে। ঘটনাটোৰ এটা ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।



ডেৰ বছৰ বৃদ্ধাশ্ৰমত আছিল শিৱচৰণ

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মুম্বাইৰ বাসিন্দা শিৱচৰণ ৰামৰতন গুপ্তাই প্ৰায় ডেৰ বছৰ ধৰি সোণিপতৰ বৃদ্ধাশ্ৰমটোত বাস কৰি আছিল। তেওঁৰ পত্নী মীনাৰো ইয়াতেই মৃত্যু হৈছিল। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱচৰণে বৃদ্ধাশ্ৰমতেই জীৱনৰ শেষ সময় কটাইছিল।

তেওঁৰ কন্যাসকল নেপাল, মুম্বাই আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ত বাস কৰে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে। মৃত্যুৰ প্ৰায় ২০ দিন পূৰ্বে পৰা কন্যাসকলে পিতৃ অসুস্থ হৈ থকাৰ

কথা জানিছিল। তথাপি তেওঁলোক পিতৃক চাবলৈ আহিব নোৱাৰিলে। আনকি মৃত্যুৰ আগৰ কেইদিনমানত ফোনযোগে যোগাযোগো বন্ধ হৈ গৈছিল বুলি কোৱা হৈছে।

সন্তানক পঢ়াইছিল দুগৰাকী কন্যা শিক্ষক

শিৱচৰণে নিজৰ সন্তানসকলক শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁৰ দুগৰাকী কন্যা শিক্ষক হিচাপেও কৰ্মৰত বুলি প্ৰতিবেদনটোত উল্লেখ আছে। কিন্তু পিতৃৰ অসুস্থতাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে সোণিপতলৈ আহিব নোৱাৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়।

পিতৃৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ

পিছতো দূৰত্বৰ কাৰণ দেখুৱাই শেষকৃত্যত উপস্থিত নহোৱাৰ কথা জনোৱা হয়।

৫১০০ টকা আৰু এটা ভিডিঅ’ কল

কন্যাসকলে শেষকৃত্যৰ বাবে ৫১০০ টকা পঠিয়াই দিয়ে আৰু সকলো কাম ভালদৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ কয়। তাৰ পিছত ভিডিঅ’ কলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পিতৃৰ অন্তৰ্বেষ্টিক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰে।

ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোত এগৰাকী কন্যাই শেষকৃত্য সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ আৰু কিমান সময় লাগিব বুলি সোধা শুনা যায়। এই কথাই সামাজিক মাধ্যমত অধিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে।

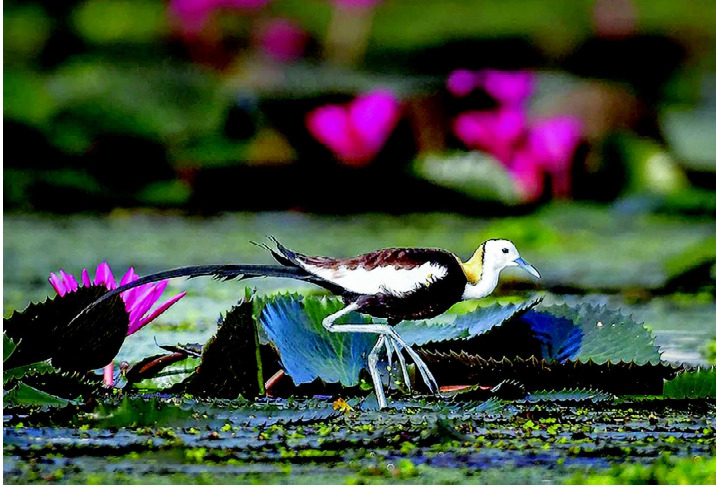
ঘটনাই উত্থাপন কৰিছে ডাঙৰ সামাজিক প্ৰশ্ন

ঘটনাটোক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বহু লোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে। কোনোবাই কন্যাসকলৰ আচৰণক অমানৱীয় বুলি সমালোচনা কৰিছে, আন কোনোবাই বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰতি সন্তানৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন তুলিছে।

অৱশ্যে এই ঘটনাক কেৱল কন্যাসকলৰ দোষ-গুণৰ বিচাৰত সীমাবদ্ধ নাৰাখি বৃহত্তৰ সামাজিক প্ৰশ্ন হিচাপেও চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। সন্তানসকলৰ কৰ্মজীৱন, ভৌগোলিক দূৰত্ব আৰু পৰিয়ালৰ পৰিৱৰ্তিত গাঁথনিৰ মাজত বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃৰ সুৰক্ষা, সংগ আৰু মানসিক প্ৰয়োজন কেনেকৈ নিশ্চিত কৰা হ’ব-সেই প্ৰশ্নটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ।

পিতৃ-মাতৃৰ শেষ সময়ত শাৰীৰিকভাৱে কাষত থাকিব নোৱাৰাৰ বহু বাস্তৱিক কাৰণ থাকিব পাৰে। কিন্তু এই ঘটনাই অন্তত এটা কথা মনত পেলাই দিয়ে-বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ-মাতৃৰ প্ৰয়োজন কেৱল ধন নহয়, তেওঁলোকক সময়, সংগ, মৰম আৰু আপোনজনৰ উপস্থিতিও প্ৰয়োজন।

শেষকৃত্যৰ খবৰ পঠিয়াই দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰি, কিন্তু আপোনজনৰ হাতখন ধৰি শেষ বিদায় জনোৱাৰ অনুভূতি কোনো ধনেৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰি।



পশ্চিমবংগৰ নদীয়া জিলাৰ এটা জলাশয়ত ফুলি থকা জলশালুকৰ মাজত পদুমপাতত খোজ কাঢ়ি যোৱা এটা ফেজেণ্ট-টেইলড জাকানা চৰাইৰ মনোমোহা দৃশ্য।

বৰেণ্য অভিনেত্ৰী মালয়া গোস্বামীলৈ 'ভবেন বৰুৱা বঁটা ২০২৬'

নলবাৰী: অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী মালয়া গোস্বামীক অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ, নাট্য আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা দীৰ্ঘদিনীয়া অৱদানৰ বাবে 'ভবেন বৰুৱা বঁটা ২০২৬' প্ৰদান কৰা হ'ব। অহা ৩ ছেপ্টেম্বৰত নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এক বিশেষ অনুষ্ঠানত তেওঁক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ নলবাৰী জিলা সমিতিয়ে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ভবেন বৰুৱাৰ স্মৃতিত ২০০৯ চনত এই বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে কলা-সংস্কৃতি আৰু সৃষ্টিশীল ক্ষেত্ৰলৈ উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই সন্মানেৰে সন্মানিত কৰি অহা হৈছে। এইবাৰৰ বঁটাত ১৫ হাজাৰ টকাৰ নগদ ধন, মানপত্ৰ, স্মাৰক, শৰাই, গামোচা আৰু চেলেং থাকিব। নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভবেন বৰুৱা সৰ্বঅসম ভিত্তিক শিশু নাট প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত মালয়া গোস্বামীক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব।



গদৰ'ৰ দৰে নহয় 'বাটৰাৰা ১৯৪৭'

জন জন বিচাৰ

...নতুন দিল্লী

বলীউডৰ অভিনেতা সানী দেওল পুনৰ এক শক্তিশালী চৰিত্ৰৰে কপালী পদালৈ উভতি আহিছে। পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষীৰ নতুন ছবি 'বাটৰাৰা ১৯৪৭'ক লৈ ইতিমধ্যে দৰ্শকৰ

দেওলৰ চৰিত্ৰটোক ছুপাৰহিৰোৰ সৈতে তুলনা কৰি কয় যে তেওঁ ছবিখনৰ বাবে সৃষ্টি কৰা চৰিত্ৰটোক ছুপাৰমেন, আইবনমেন আৰু আন বহু ছুপাৰহিৰোতকৈও শক্তিশালী বুলি ভাবে। তেওঁৰ মতে, কট্টৰপন্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো সাধাৰণ যুঁজতকৈ বহু কঠিন।

বাটৰাৰা ১৯৪৭'ৰ জৰিয়তে



মাজত যথেষ্ট চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। অৱশ্যে ছবিখনক সানী দেওলৰ জনপ্ৰিয় ছবি 'গদৰ: এক প্ৰেম কথা'ৰ সৈতে তুলনা কৰা বিষয়টোত পৰিচালক সন্তোষীয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে দুয়োখন ছবিৰ কাহিনী আৰু নায়কৰ উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ পৃথক।

সন্তোষীৰ মতে, 'গদৰ'ত তাৰা সিঙে নিজৰ পৰিয়াল আৰু পত্নীক উদ্ধাৰৰ বাবে যুঁজিছিল। কিন্তু 'বাটৰাৰা ১৯৪৭'ত সানী দেওলৰ চৰিত্ৰটোৱে এক বৃহত্তৰ উদ্দেশ্যক লৈ যুঁজ কৰে। তেওঁ কয় যে এই চৰিত্ৰটো কেৱল কোনো ব্যক্তি, দল বা সেনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা নায়ক নহয়; তেওঁ কট্টৰপন্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা এক চৰিত্ৰ।

পৰিচালক গৰাকীয়ে সানী

পৰিচালক ৰাজকুমাৰ সন্তোষী আৰু সানী দেওলে প্ৰায় ৩০ বছৰৰ পিছত পুনৰ একেলগে কাম কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুয়োৰে যুটিয়ে 'ঘায়ল' আৰু 'ঘাতক'ৰ দৰে ছবিৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছিল। ছবিখনত সানী দেওলৰ সৈতে প্ৰীতি জিন্টা, কৰণ দেওল আৰু শ্বাবানা আজমীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। ছবিখন ১৪ আগষ্টত দেশৰ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব।

'গদৰ'ৰ দেশপ্ৰেম আৰু একচনধৰ্মী পৰম্পৰাৰ সৈতে তুলনা হ'লেও 'বাটৰাৰা ১৯৪৭'ৰ কাহিনী আৰু সানী দেওলৰ চৰিত্ৰই এক পৃথক সামাজিক আৰু মতাদৰ্শগত সংস্কাৰক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়িছে বুলি পৰিচালকে স্পষ্ট কৰিছে।

ভোজপুৰী গানৰ বাহিৰেও আছে বিহাৰৰ সমৃদ্ধ লোকসংগীত

জন জন বিচাৰ

...নতুন দিল্লী

বিহাৰৰ গান বুলি ক'লেই বহু লোকৰ মনলৈ প্ৰথমে ভোজপুৰী জনপ্ৰিয় গানৰ কথাই আহে। কিন্তু বিহাৰৰ সংগীতৰ পৰম্পৰা তাৰ বহু ওপৰত বিস্তৃত। ৰাজ্যখনৰ মৈথিলী, ভোজপুৰী, বঙ্গিকা, অংগিকা আৰু মগহী আদি বিভিন্ন ভাষা-উপভাষাত প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি লোকগীতৰ সমৃদ্ধ পৰম্পৰা চলি আহিছে।

বিহাৰৰ লোকগীত কেৱল মনোৰঞ্জনৰ মাধ্যম নহয়; ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে মানুহৰ জন্ম, বিবাহ, কৃষিকাৰ্য, উৎসৱ, প্ৰেম, বিৰহ, প্ৰব্ৰজন আৰু বিদায়ৰ অনুভূতি। জীৱনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো বিশেষ মুহূৰ্তৰ বাবেই ইয়াত একো একোটা বিশেষ লোকগীত আছে।

জন্মৰ আনন্দত 'সোহৰ'

ঘৰত সন্তান জন্ম হ'লে মহিলাসকলে গোৱা 'সোহৰ' বিহাৰৰ অন্যতম পৰিচিত লোকগীত। নৱজাত শিশুৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু মংগল কামনা কৰাৰ লগতে পৰিয়ালৰ আনন্দ-উৎসৱো এই গীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায়। 'জুগ-জুগ জয় সু ললনৰা'ৰ দৰে পৰম্পৰাগত সোহৰৰ আজিও বহু অঞ্চলত শুনিবলৈ পোৱা যায়।

বিবাহৰ সৈতে 'কোহৰ'

আৰু 'সমাদি' বিহাৰৰ বিবাহ পৰম্পৰাতো লোকগীতৰ বিশেষ স্থান আছে। দৰা-কইনা কোহৰৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত গোৱা 'কোহৰ' গীত

নৱদম্পতীৰ সুখী আৰু মংগলময় জীৱনৰ বাবে আশীৰ্বাদ জনোৱা হয়। আনহাতে, কন্যাৰ বিদায়ৰ সময়ত গোৱা 'সমাদি' গীতত পিতৃ-মাতৃৰ মৰম, কন্যাক বিদায় দিয়াৰ বেদনা আৰু বিচ্ছেদৰ অনুভূতি প্ৰকাশ পায়। বিশেষকৈ মিথিলাঞ্চলত এই পৰম্পৰা অতি জনপ্ৰিয়।

ছট পূজাৰ গীতেৰে

ভক্তি পৰিৱেশ

বিহাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে ছট পূজাৰ গীত গভীৰভাৱে জড়িত। কাৰ্তিক মাহত ছট পূজাৰ সময়ত ঘৰ-দুৱাৰ, পথ-ঘাটৰ পৰা নদীৰ ঘাটলৈকে ভক্তিমূলক গীতৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যায়।

শাৰদা সিনহাৰ কণ্ঠত জনপ্ৰিয় হোৱা 'কাঁচি হি বাঁহ কে বহংগিয়া' আৰু 'উগি হে দীনানাথ' আদি গীতে ছট উৎসৱৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশক অধিক গভীৰ কৰি তোলে। এই গীতসমূহত ছটা মাইয়া আৰু সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতি ভক্তি আৰু প্ৰাৰ্থনা প্ৰকাশ পায়।

সাবনত 'কজৰী'

চৈত মাহত 'চৈতী'

ঋতুৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতেও বিহাৰৰ লোকসংগীতৰ গভীৰ সম্পৰ্ক আছে। সাবন মাহত 'কজৰী' গোৱা হয়। বৰষুণৰ সৌন্দৰ্য, প্ৰেম আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বেদনা কজৰী গীতৰ মূল বিষয়। আনহাতে চৈত মাহত 'চৈতী' গীতৰ পৰম্পৰা দেখা যায়। বসন্তৰ আগমন, প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য আৰু আনন্দৰ অনুভূতি এই গীতসমূহত প্ৰতিফলিত হয়।

প্ৰব্ৰজনৰ বেদনা 'বিদেশিয়া'ত

বিহাৰৰ লোকসংগীতৰ ভিতৰত 'বিদেশিয়া' এক বিশেষ ধাৰা। বিখ্যাত লোকশিল্পী আৰু নাট্যকাৰ তিখাৰী ঠাকুৰে বিদেশিয়া পৰম্পৰাক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল। কামৰ সন্ধানত গাঁও এৰি আন চহৰলৈ যোৱা শ্ৰমিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজৰ বিচ্ছেদ, অপেক্ষা, বিৰহ আৰু সামাজিক সমস্যাই বিদেশিয়া গীতৰ মূল বিষয়।

পথাৰত শ্ৰমৰ সংগী 'ৰোপনী গীত'

ধান ৰোপণৰ সময়ত বিহাৰৰ মহিলাসকলে গোৱা 'ৰোপনী গীত' গ্ৰাম্য জীৱনৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা। পথাৰত একেলগে কাম কৰাৰ সময়ত গোৱা এই গীতসমূহে শ্ৰমৰ ক্লান্তি ক্ৰমাৱৰ্ত লগতে আনন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। বহু গীতত ভাল বৰষুণ আৰু কৃষিৰ বাবে ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনাও কৰা হয়।

লোকগীতত জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ ছবি

বিহাৰৰ লোকসংগীত আচলতে বিহাৰৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ এখন জীৱন্ত দলিল। শিশুৰ জন্মৰ আনন্দৰ পৰা কন্যাৰ বিদায়ৰ চকুপানীলৈ, বিবাহৰ মংগলকামনাৰ পৰা কৃষকৰ শ্ৰমলৈ, ছট পূজাৰ ভক্তিৰ পৰা প্ৰব্ৰজনৰ বেদনালৈ জীৱনৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অনুভূতিয়েই এই লোকগীতসমূহত স্থান পাইছে।

সেয়েহে বিহাৰৰ সংগীতক কেৱল আধুনিক ভোজপুৰী জনপ্ৰিয় গানৰ মাজতে সীমাবদ্ধ কৰি চোৱা উচিত নহয়।

Akhilesh Redefines PDA, Says 'P' Stands for Pandit



Lucknow: The Samajwadi Party held a show of strength in Lucknow on the birth anniversary of socialist leader Janeshwar Mishra. Addressing a party conference aimed at reaching out to the Brahmin community, SP chief Akhilesh Yadav offered a new interpretation of the party's PDA formula, saying the 'P' could also stand for Pandit.

Yadav said the SP would seek to unite different social groups ahead of the 2027 Uttar Pradesh Assembly elections and claimed that political change in the state was inevitable.

Former minister Abhishek Mishra also accused the BJP government of carrying out alleged fake encounters targeting Brahmins and promised an investigation if the SP returned to power.

VOICE OF ALL, FOR ALL

WEEKLY

JAN JAN VICHAR

Guwahati, Friday, 7 August 2026

15

Centre Assures Full Flood Relief Support

Jan Jan Vichar

...Sivsagar

Union Health Minister J.P. Nadda on Wednesday assured Assam of complete support from the Centre for relief and rehabilitation as devastating floods continue to affect large parts of the state. During his visit to flood-hit areas of Sivasagar district, Nadda said there would be 'no shortage' of relief assistance and that the Union government was committed to helping affected families rebuild their lives.

Accompanied by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Nadda visited Bihubor and Nepali Khuti, among the worst-affected areas, and interacted with families who have lost homes, household belongings, crops, livestock and sources of livelihood.

Speaking to residents, Nadda said the Centre was extending complete financial assistance to Assam and that central teams were already



assessing the extent of damage. He said the Union government was fully engaged in relief and rehabilitation efforts.

The assurance comes at a critical time for thousands of flood-affected families who are now facing the difficult task of rebuilding their homes and livelihoods. In several areas, residents have been forced to leave their homes and seek shelter in relief camps or on higher ground.

The immediate challenge

is no longer limited to rescue and relief. Rehabilitation, restoration of livelihoods and rebuilding damaged infrastructure will determine how quickly affected communities recover.

The Assam government is continuing relief distribution and damage assessment across Sivasagar and other flood-hit districts. Assistance has also been announced for damaged houses, crop losses, livestock and livelihood restoration.

Ajmal's Sharp Attack on Assam Government

Barpeta: AIUDF president and prominent Assam politician Badruddin Ajmal launched a sharp attack on the BJP-led Assam government, urging political leaders to rise above religious divisions and put humanity at the centre of public life. During his visit to Barpeta district, Ajmal criticised what he described as attempts to divide people in the name of religion. He questioned the continued political emphasis on Hindu-Muslim differences and called upon leaders to recognise that people's basic identity is ultimately human.

"You will neither become Hindu nor Muslim; you are the children of human beings," Ajmal said, while questioning when those making divisive statements would understand the importance of humanity.

In an unusually aggressive remark, the AIUDF chief said those promoting such politics should first learn to behave like human beings. He accused them of being 'worse than animals' and urged political leaders to stop repeatedly invoking Hindu-Muslim divisions.

Akhil Gogoi Praises Himanta's Flood Response

Jan Jan Vichar

...Guwahati

In a rare display of political appreciation cutting across sharp ideological differences, Rajbor Dal president and Sivasagar MLA Akhil Gogoi praised Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma for personally entering severely flooded areas to assess the situation on the ground.

Gogoi, one of the strongest critics of the BJP-led Assam government, accompanied the Chief Minister during his visit to flood-hit parts of Sivasagar. He described Sarma's de-

cision to walk barefoot through waist-deep floodwater as an unprecedented moment in Assam's political history.

Gogoi said the visit allowed the Chief Minister to see the devastation directly rather than through a carefully managed inspection. He expressed satisfaction that he could show Sarma the actual conditions faced by residents, without what he described as 'red-carpet arrangements' or an inspection from the safety of heavy machinery.

Political Rivalry Takes a Back Seat



The Sivasagar MLA said he personally held the Chief Minister's hand and guided him through the inundated area towards Phuleshwari School, which was sur-

rounded by deep floodwater.

While political differences between Gogoi and Sarma remain sharp, his public acknowledgement of the Chief Minister's efforts stands out at a time when Assam is battling a severe flood situation across several districts.

Sarma has been touring flood-affected areas of Upper Assam, including Sivasagar and Charaideo, inspecting relief operations and interacting with affected families. Homes, roads, ag-

ricultural fields and livelihoods have suffered extensive damage in the deluge.

The episode also highlights an important principle of disaster management: political differences can wait when people are in distress. What matters first is reaching affected citizens, understanding their suffering and ensuring timely relief and rehabilitation.

Gogoi's praise may be politically unusual, but it sends a powerful message—the flood crisis demands cooperation, accountability and action beyond party lines.

Seven Assam Girls Return Home After Bihar Brick Kiln Ordeal

Jan Jan Vichar
...Dhubri

Seven minor girls from Assam's Dhubri district, rescued from a brick kiln in Bihar after allegations of exploitation and abuse, have finally returned home after spending several months in a government shelter in Saharsa.

The girls were brought back to Dhubri under Bihar Police escort and subsequently handed over to the Child Welfare Committee (CWC) after completion of the required legal formalities. Officials said the survivors will now be placed under the care of their respective legal guardians, with child protection authorities monitor-

ing their rehabilitation and safety.

The girls were among 47 workers from economically vulnerable families in Dhubri, including adults and children, who had travelled to Bihar around five to six months ago in search of employment at a brick kiln in Saharsa district. The case came to light in April after workers allegedly complained of confinement, forced labour, non-payment of wages and harsh treatment. The allegations also included serious abuse of the seven minor girls. Bihar Police subsequently arrested the alleged kiln owner, and criminal proceedings against him and his associates are continuing under relevant laws, including pro-

visions of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.

The rescue operation followed an incident in March in which a woman worker was allegedly shot in the leg. Several labourers managed to escape and approached local residents and the police, leading to intervention by the authorities. While the other rescued workers returned to Dhubri in April, the seven girls remained in the Bihar shelter home for medical care, protection and assistance while the investigation and statutory procedures continued. Dhubri child protection officials said authorities in Assam and Bihar worked together to complete verification and repa-

triation procedures. Officials will also conduct regular home visits to monitor the girls' welfare and rehabilitation.

The tragedy exposes the vulnerability of poor families who migrate in search of livelihood and can fall prey to exploitative labour networks. For these seven girls, returning home is only the beginning. Justice must follow rescue, and rehabilitation must go beyond paperwork. The authorities must ensure continued protection, education, counselling and livelihood support for their families while bringing all those responsible to justice. No child should have to leave home in search of livelihood only to become a victim of exploitation.

Tamil Nadu Sets Aside Rs 1,000 Crore for Gifts

Chennai : The C. Joseph Vijay-led Tamil Nadu government has allocated over Rs1,000 crore in its maiden Budget to fulfil election promises through a range of welfare gift schemes. Under the 'Thai Maaman Thanga Mothiram Thittam', every newborn delivered in a government hospital will receive a 1-gram gold ring, with Rs 560 crore earmarked for the scheme. Another Rs 812 crore has been allocated to provide women with an 8-gram gold coin and silk saree at marriage. The government will also provide free milch cows to 10,000 eligible women annually and offer subsidised goat and sheep rearing support to vulnerable groups.

Assam's Hidden World Beneath the Ground New Blind Eel Species Discovered in Goalpara

Jan Jan Vichar
...Goalpara

Assam has once again emerged as a centre of remarkable biodiversity with the discovery of a new species of underground blind eel in Goalpara district. The discovery by a team of Indian and German researchers has opened a window into a mysterious subterranean ecosystem believed to exist beneath the groundwater aquifers of Northeast India.

The newly identified species, named *Rakthamichthys anchi*, is a reddish, earthworm-like blind eel measuring between 25.5 cm and 31.8 cm in length. It was discovered in wells in a village in Goalpara and appears to live permanently underground, away from sunlight.

The research, published in the international peer-reviewed journal *Zootaxa*, was conducted by ichthyologists from Germany's Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden and researchers from Assam Don Bosco University



Scientists Find *Rakthamichthys anchi* in Underground Wells, Pointing to a Previously Unknown Ecosystem Beneath Northeast India's Floodplains

and Dhanamanjuri University, Imphal.

The name 'anchi', meaning 'red' in the Garo language, refers to the species' distinctive reddish body. Researchers noted that the creature apparently has no visible eyes, an adaptation that reflects its life in complete darkness.

Genetic analysis indicates a significant difference between the newly discovered species and related species found in other parts of India. Researchers have so far found *R. anchi* in only two wells in a single village. The exact location has deliberately not been disclosed to protect the fragile popu-

lation from disturbance and potential exploitation.

What makes the discovery even more significant is that it follows another extraordinary finding from the same village. Earlier this year, researchers identified *Gitchak nakana*, described as the first known miniature subterranean blind fish, from the same locality.

The discovery of two highly unusual underground fish species in one small area suggests that Goalpara may harbour a rich and largely unexplored subterranean ecosystem beneath its alluvial floodplains.

Scientists say permanent un-

derground life is extremely rare among fish. Of more than 37,500 described fish species worldwide, only a little over 300 are known to have adapted to permanent subterranean habitats.

For Assam, the discovery is more than a scientific curiosity. It is a reminder that the state's biodiversity extends far beyond its forests, wetlands and rivers. Even beneath ordinary village wells, unknown forms of life may be surviving in ecosystems that science has only just begun to understand.

The findings also underline the urgent need to protect groundwater habitats and conduct further research. Development, groundwater extraction and environmental changes could threaten species that exist only in highly specialised underground conditions.

The real significance of the Goalpara discovery may therefore lie not simply in naming another species, but in revealing an entire hidden world beneath Assam's soil—one that could contain many more secrets waiting to be discovered.

India's GI Map Expands Rapidly : Margherita

“Over 600 New GI Tags Added in 12 Years”

Jan Jan Vichar

...New Delhi

India's Geographical Indication (GI) landscape has witnessed a major expansion over the past 12 years, with the number of GI-tagged products cross-

property certification. According to him, it represents the identity, cultural heritage, regional uniqueness and civilisational strength associated with a particular product.

GI recognition is particularly important for India

crafts, agricultural products, textiles, food items and other region-specific goods can generate employment and strengthen rural economies when they are effectively marketed and connected to wider markets.

However, obtaining a GI tag should not be treated as the final achievement. The real challenge lies in ensuring that the artisan, farmer, producer and local community actually benefit from the recognition.

Better branding, quality control, packaging, e-commerce access, tourism promotion and international marketing will be necessary to convert GI recognition into sustainable income.

The 'GI & Beyond 2.0' Summit focused on increasing the visibility, value and market potential of India's GI-tagged products.

For a country as culturally diverse as India, every GI product represents more than a commercial commodity—it represents a story of a place, its people and its traditions. The next step must be to ensure that these stories reach global markets while the communities that created them receive a fair share of the economic benefits.



ing 820, Minister of State for External Affairs Pabitra Margherita said on Wednesday.

Speaking at the 'GI & Beyond 2.0' Summit in New Delhi, Margherita said India had around 200 GI-tagged products until 2014, while more than 600 additional products have received the recognition since then.

The minister said a GI tag should not be viewed merely as an intellectual

because many of the country's traditional products are closely linked to specific regions, communities and generations of indigenous knowledge. Such recognition can help protect these products from imitation while giving local producers greater visibility in domestic and international markets.

The expansion of GI registrations also presents a significant economic opportunity. Traditional handi-

NEWS IN BRIEF



TVK MLA MR Pallavi arrives to attend the presentation of Tamil Nadu government's maiden budget during the Assembly session, at Fort St. George in Chennai.

CJP to Remain Pressure Group

New Delhi: The Cockroach Janta Party (CJP) will function as a pressure group for the time being, founder Abhijeet Dipke said ahead of the organisation's core team meeting in Chhatrapati Sambhajnagar, Maharashtra. The meeting will discuss issues including declining public trust in institutions, unemployment and ethanol-blended fuel. CJP leaders also plan to continue pressing the government to withdraw FIRs registered against students who participated in the recent protests over the NEET-UG paper leak and other examination irregularities. CJP spokesperson Saurav Das said the group would seek legal and medical assistance for protesters injured during the agitations. He also confirmed that activist Sonam Wangchuk would continue as the organisation's mentor.

RBI Holds Repo Rate at 5.25% for Third Time

Jan Jan Vichar

...New Delhi

The Reserve Bank of India (RBI) kept the repo rate unchanged at 5.25 per cent for the third consecutive policy meeting, opting for stability amid continuing uncertainty in global energy prices, trade and financial markets.

The Monetary Policy Committee (MPC) unanimously decided to maintain

the repo rate at 5.25 per cent and retained its neutral policy stance, signalling that the central bank wants flexibility to respond to changing economic conditions.

The Standing Deposit Facility rate remains at 5 per cent, while the Marginal Standing Facility and bank rate continue at 5.5 per cent.

RBI Governor Sanjay Malhotra said the prolonged crisis in West Asia has created uncertainty around

crude oil prices and financial markets. Persistent trade concerns, including new tariffs imposed by the United States, have added another layer of risk for the Indian economy. The decision also comes against the backdrop of rising retail inflation. Consumer Price Index-based headline inflation increased to 4.38 per cent in June, moving above the RBI's medium-term target of 4 per cent. For ordinary borrow-

ers, however, the rate pause offers an important measure of predictability. Existing floating-rate home and other loans are less likely to face an immediate change in borrowing costs, while prospective homebuyers can plan purchases with greater certainty. The real estate sector has welcomed the decision, saying stable interest rates could support housing demand, construction activity, MSMEs and employ-

ment.

But the RBI faces a delicate balancing act. It must protect economic growth without allowing external shocks—particularly oil prices and supply disruptions—to push inflation higher. The message from the central bank is clear: India's economy remains resilient, but global uncertainties demand caution. For now, stability has taken priority over another rate cut.

EDITORIAL By-Poll Setbacks

Three Assembly by-election results may not change the national political arithmetic, but they can change the political mood. For the BJP, the defeats in Bihar's Bankipur and Madhya Pradesh's Datia are not ordinary setbacks. They are warning signals that a party accustomed to winning may be beginning to underestimate voter dissatisfaction.

The Bankipur defeat is particularly significant. Losing a seat held by the BJP for 31 years (and associated with the party's national president) is not merely a statistical loss. It suggests that

organisational strength and past loyalty cannot indefinitely substitute for performance, credibility and local engagement.

Prashant Kishor's victory for the Jan Suraj Party is equally significant. One by-election does not make a new political force, but it proves that voters are willing to experiment when established parties fail to inspire confidence. Opposition parties should not dismiss this opportunity. The BJP also needs to examine the message from Datia. Candidate selection, factionalism and local leadership cannot be treated as minor organisational issues. Elections are won on the ground, not in television studios or social-media campaigns.

More importantly, the party must con-

front growing public questions over governance, accountability and administrative responsiveness. Controversies surrounding major institutions and public issues can accumulate even when they do not immediately produce electoral punishment.

The BJP's greatest strength has always been its organisational discipline and ability to read political signals. This is precisely why it should take these results seriously. The danger is not losing three by-elections. The danger is refusing to understand why they were lost.

If the BJP mistakes electoral dominance for permanent public approval, today's by-poll warning could become tomorrow's political reckoning.

Why an 850-seat Lok Sabha threatens Indian democracy

—Jan Jan Vichar

...Shashi Tharoor

The government's seeming determination to proceed with a revised delimitation that drastically increases the size of the Lok Sabha to 824 or 850 seats marks a disastrous watershed in India's institutional architecture. The underlying justification offered by the government is purely mathematical: The size of the Lower House cannot remain frozen at the 543-seat limit established in 1972, since when the nation's population has more than doubled. Yet, beneath this seemingly democratic argument lies a profound hazard.

Amid all the other major challenges of the looming delimitation exercise - notably the severe political and federal friction caused by penalising southern states for successful population control, while disproportionately rewarding the northern Hindi heartland for its failures - a basic question remains unaddressed: Does it make any sense to have a legislature so massive and structurally unwieldy? No established democracy does.

Every mature democratic system recognises that a Parliament must be capped at a size that permits genuine legislative scrutiny, cohesive debate, and individual member participation. By choosing to push the Lok Sabha towards 850 seats (a size no other democratic legislature has), India is charting an anomalous and dangerous course. Democratic theory and global practice consistently show that beyond a threshold, a legislature ceases to function as a deliberative body and deteriorates into a chaotic colosseum where only a select few can speak, while the rest are reduced to passive spectators, mere numbers on voting ma-

chines.

After all, the United States House of Representatives was legally capped at 435 in 1929, when the United States population stood at 120 million. Today, the American population has tripled to over 335 million, yet the size of the House remains at 435. Americans recognise that increasing the number of representatives to match population growth would paralyse the legislative process. Instead, each member simply represents a larger number of voters, relying on robust local staff, modern communication, and a highly organised committee system to bridge the governance gap. Indian MPs can do that too.

The realities of an 850-member Lok Sabha are devastating for individual legislators. In a standard parliamentary session, time is an unyielding, scarce resource. Consider the daily Question Hour or a standard legislative debate on a complex bill. If a debate is allocated four hours, and time is distributed according to party strength, at most 15-20 MPs out of 850 will be able to participate. In practice, backbenchers and members of smaller parties will be mostly silenced.

With an oversized Parliament, a vast majority of MPs will never get to ask a question, initiate a private member's bill, or participate in a substantive debate during their entire five-year tenure. They will be transformed into silent placeholders, raising their hands when the party commands. This will worsen an already distressing trend in Indian governance: The shrinking role (and systemic degradation) of Parliament. In recent years, the number of days Parliament meets annually has steadily declined, bills have been passed via voice vote within min-

utes without standing committee scrutiny, and the Opposition is frequently sidelined. Flooding the chamber with hundreds of additional members will accelerate this marginalisation, burying quality under the sheer weight of quantity.

An oversized legislature where the vast majority of members have no voice suits an executive that prefers compliance over scrutiny. When a Parliament becomes too large to debate, it naturally cedes its oversight power to the executive cabinet. The individual lawmaker loses leverage, and the House is reduced to a notice-board and a rubber-stamp.

This structural transformation bears an ominous resemblance to the authoritarian legislative model in Beijing or Pyongyang. Specifically, an 850-seat Lok Sabha risks becoming a desi version of the Chinese People's Political Consultative Conference or the North Korean Supreme People's Assembly - enormous, unwieldy bodies designed to look grand, representative, and pluralistic, but reduced to applauding set speeches by the Great Leader. Their sheer size guarantees they cannot engage in real legislative negotiation or challenge the ruling executive. They exist to perform consensus, not to build it through debate. If India builds a massive legislature where MPs are stripped of their voices due to the arithmetic of time constraints, it will have successfully hollowed out its democracy, replacing a vibrant deliberative body with a performative pageant. Far better to save the extra expenditure on salaries, accommodation, travel and pensions for 300 more MPs and instead build a serious office building for the existing MPs near Parliament, as every other democracy provides its legislators.

The government's primary defence - that a single MP cannot effectively represent two to three million citizens - is a fallacy that misinterprets the role of a national lawmaker. An MP's constitutional duty is national legislation, foreign policy, macroeconomic governance, and holding the Union executive accountable. They are not municipal councillors or MLAs. If India established a sharp, institutional demarcation between the roles of Members of Legislative Assemblies (MLAs) and Members of Parliament (MPs), a smaller, focused group of MPs could easily represent large constituencies. Local grievances, municipal infrastructure, and civic amenities fall squarely within the domain of state legislatures and local panchayats or municipal corporations under the 73rd and 74th Amendments; as population increases, expand the number of MLAs! If local governance frameworks are empowered, the local citizen does not need to look to an MP for everyday civic needs. By keeping the Lok Sabha compact and focused on national governance, and leaving localised representation to state and municipal levels, India could maintain a highly efficient, effective, and truly participative federal structure, without ruining the functionality of Parliament.

The proposal to expand the Lok Sabha to 850 would create a House that is not a forum for governance but an echo chamber for the government. As we contemplate the future of our democracy, we must realise that true representation lies in the quality of debate, the rigour of legislative committee scrutiny, and the empowerment of local levels of government - not in creating an unwieldy megachamber that replaces democratic discourse with empty theatre.

Jan Jan Vichar The Student's Corner Board Exam Focus

1. Background of the Partition of Bengal

At the beginning of the twentieth century, the Indian national movement was becoming stronger. People were increasingly demanding freedom from British rule. Bengal was one of the most important centres of nationalism. Newspapers, students, intellectuals and political organisations were actively spreading nationalist ideas.

At this time, Lord Curzon was the Viceroy of India. In 1905, his government decided to divide the large province of Bengal.

The British government gave an administrative reason for the partition. It argued that Bengal was too large to administer efficiently. However, Indian nationalists believed that the real purpose was to weaken the nationalist movement and divide Indians.

This policy was commonly understood as 'Divide and Rule'.

2. Partition of Bengal-1905

The Partition of Bengal came into effect on **16 October 1905**.

Bengal was divided mainly into: Eastern Bengal and Assam, with Dacca as its capital. The remaining part of Bengal, with Calcutta as its capital.

The partition created widespread anger among Indians.

People believed that the British were deliberately creating divisions between different communities, particularly between Hindus and Muslims, to weaken Indian unity.

Therefore, the partition became an important turning point in the Indian freedom movement.

3. Beginning of the Swadeshi Movement

The strongest response to the partition was the Swadeshi Movement. The word Swadeshi means 'of one's own country.'

The basic idea was:

ASSEMB :: Class X :: Social Science :: History :: Chapter 1 Partition of Bengal (1905–1911) and the Swadeshi Movement



Use Indian goods and boycott foreign goods.

People stopped buying British-made products, especially foreign cloth. They encouraged Indian industries, handicrafts, handlooms and locally produced goods.

The boycott became a powerful political weapon because it directly affected British economic interests.

People organised:

Public meetings
Processions
Boycott campaigns
Demonstrations
Bonfires of foreign cloth
Picketing of shops selling foreign goods

The movement gradually spread beyond Bengal and helped strengthen Indian nationalism.

4. Role of Students and Women

The Swadeshi Movement was not restricted to political leaders. Students actively

participated in demonstrations, boycotts and nationalist activities. Many students left government-controlled educational institutions and joined national educational institutions.

Women also began participating more actively in public political activities. They joined meetings, processions and campaigns encouraging the use of Swadeshi products.

This was important because nationalism was gradually becoming a movement involving ordinary people rather than only political leaders.

5. National Education

The Swadeshi leaders believed that British-controlled education was not sufficient for creating patriotic citizens. Therefore, they promoted national education. The National Council of Education was established in 1906. The

aim was to provide education that would:

Develop patriotism.

Encourage scientific and technical knowledge.

Promote Indian culture.

Create self-confidence among students.

Reduce dependence on British educational institutions.

National schools and colleges were established in different places.

6. National Literature and Culture

Literature, songs, poems and newspapers became important tools of the nationalist movement. Writers and poets used their work to inspire people to love their country

and oppose foreign rule.

Rabindranath Tagore played an important role in promoting unity during the anti-partition movement.

On 16 October 1905, the day the partition came into effect, people observed Raksha Bandhan as a symbol of unity and brotherhood.

Songs and patriotic writings helped create a feeling that Indians belonged to one nation.

7. Rise of National Industries

Another important result of the Swadeshi Movement was the growth of Indian industries.

People understood that political freedom would be difficult without economic strength. Therefore, Indians encouraged:

Indian textile industries
Handloom

Cottage industries

Soap and other local products

Indigenous businesses

The movement encouraged people to become economically self-reliant.

Thus, Swadeshi was not only a political movement but also an economic movement.

8. Formation of the Muslim League

During this period, another important political development took place. The All-India Muslim League was established in 1906 at Dacca. The organisation initially aimed to protect the political interests of Muslims. The British government encouraged separate political identities among communities, which contributed to the growth of communal politics.

The formation of the Muslim League became an important development in the later history of Indian nationalism.

to be continued...

When Paintings Come Alive in Song

Jan Jan Vichar
... Cultural Desk

Paintings are usually meant to be seen. But in Rajasthan, there is a remarkable tradition where paintings are not merely displayed—they are sung, narrated and performed.

Known as Phad painting, this centuries-old folk art is traditionally created on long pieces of cloth and depicts the stories of Rajasthan's folk deities. Among its most celebrated forms is the Pabuji Phad, associated with the legendary folk hero and deity Pabuji. The tradition has survived for nearly 700 years and continues to connect art, music, faith and storytelling.

Rajasthan's 700-Year-Old Pabuji Phad Tradition



A Painting That Tells a Story

Phad painting is traditionally associated with the Mewar region, particularly Bhilwara and Shahpura. Unlike paintings made on canvas or paper, Phad is created on specially prepared cotton or khadi cloth.

The word Phad is associated with the idea of unfolding or opening. Tradition-

ally, the long painted cloth was rolled up and opened during performances, revealing different scenes of a larger story.

The paintings use bold colours and detailed figures to portray battles, journeys, heroic deeds, religious episodes and stories of legendary characters.

The Story of Pabuji



Pabuji is one of Rajasthan's most revered folk heroes. He is particularly

worshipped by the Rabari community of Rajasthan and Gujarat, who regard him as a protector of their cattle and camels.

According to popular belief, Pabuji was a brave Rajput warrior who sacrificed his life while protecting cattle. Folk traditions also associate him with an incarnation of Lakshmana, the younger brother of Lord Rama.

His heroic life forms the central subject of the Pabuji Phad, with different scenes portraying his adventures, battles and devotion to protecting his people and animals.

From Painting to Performance

The most fascinating part of the Phad tradition is what happens after the painting is completed.

Traditionally, village priest-storytellers known as Bhopas, accompanied by female performers called Bhopis, would travel with the Phad. Af-

ter sunset, the painted scroll would be ceremonially unfolded. The Bhopa would then narrate and sing the story depicted in the painting, often accompanied by the ravanhatha, a traditional string instrument.

The performance was

not simply entertainment. It was considered a form of devotion and a way of invoking the deity whose story was being narrated.

For generations, these performances also served as a means of preserving history, folklore and cultural memory in

communities where stories were passed from one generation to another through oral traditions.

How Is a Phad Made?

Creating a Phad is itself an elaborate artistic process. A piece of cotton or khadi cloth is carefully prepared with a starch-like paste made from rice or flour. Once the surface becomes suitable for painting, artists begin creating intricate figures and scenes.

Traditional Phad artists have historically relied on natural and plant-based colours. Strong reds, yellows, greens, blacks and other earthy shades give the paintings their distinctive visual character.

The composition is generally crowded with figures, yet each character and scene has a specific place in the larger narrative.



A Living Heritage

Phad painting is more than an artistic style. It represents a complete cultural tradition in which painting becomes storytelling, storytelling becomes music, and music becomes devotion.

While Pabuji remains central to the tradition, contemporary Phad artists have also begun depicting stories from the Ramayana, Mahabharata and Panchatantra, allowing the art form to reach new generations.

In an age dominated by digital entertainment and rapidly changing lifestyles, Rajasthan's Phad tradition reminds us that a painting can do much more than decorate a wall—it can preserve a community's memories, beliefs and stories, and bring them alive through the human voice.

D.S. ASSOCIATES
TAX CONSULTANTS

TRUSTED ADVISORS

ONE-STOP SOLUTION

**ALL YOUR TAX & FINANCE
NEEDS UNDER ONE ROOF**

Expert, reliable and timely solutions for individuals, businesses & startups — handled by experienced professionals you can trust.

OUR SERVICES

- Income Tax Returns
- Audit
- Loans
- Company Registration
- Trademark Registration
- Subsidy Related Works

- GST Registration & Filing
- Accounting & Book Keeping
- Insurance
- Import & Export Compliance
- FSSAI Registration
- Documentation Services

...AND MANY MORE SERVICES

CONTACT US TODAY
E-Mail : dsselecttax@gmail.com

Dhaneshwar Choudhary
70026 82705

Subhash Choudhary
84728 20656